



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17, 1977/अग्रहायण 26, 1899

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17, 1977/AGRAHAYANA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1977

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1977

का० आ० 3883.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से श्री सी० बी० नन्दीश्वर के स्थान पर श्री डी० बालागोपालन, सरकार के विशेष सचिव, मंत्रीमंडल कार्य (सूनाव) विभाग को 14 नवम्बर, 1977 से अगले आदेशों तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्-द्वारा नामनिर्देशित करना है।

[सं० 154/कर्नाटक/77]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 19th November, 1977

S.O. 3883.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Karnataka, hereby nominates Shri D. Balagopalan, Special Secretary to Government, Department of Cabinet Affairs (Elections), as the Chief Electoral Officer for the State of Karnataka with effect from 14 November, 1977 vice Shri C. B. Nandeeswar.

[No. 154/Karnataka/77]

का० आ० 3884.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से श्री एम० सुब्रमण्यन के स्थान पर श्री बी० के० हाल्वे, आई० ए० एस० महाराष्ट्र सरकार के सचिव, खाद्य तथा सिविल पूर्ति विभाग, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक महाराष्ट्र राज्य के नये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करना है।

[सं० 154/महाराष्ट्र/77]

New Delhi, the 21st November, 1977

S.O. 3884.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Maharashtra, hereby nominates Shri B. K. Halve, IAS. Secretary to Government, Food and Civil Supplies Department, as the Chief Electoral Officer for the State of Maharashtra with effect from the date he takes over charge and until further orders vide Shri M. Subramanian.

[No. 154/MT/77]

आदेश

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1977

का० आ० 3885.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 2. मोरमुगाओ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पावस्कर रत्नाकांत रामचन्द्र, पटेल हाऊस, ऐक्वम पोस्ट, मारगो-गोवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायोज्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पावस्कर रत्नाकांत रामचन्द्र को समक्ष के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है।

[स० गोवा-लोक० सभा/2/77]

आई० के० के० मेनन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd November, 1977

S.O. 3885.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pavaskar Ratnakant Ramchandra, Patel House, Aquem Post, Margao-Goa, who was a contesting candidate for General Election to the House of the People, 1977 from 2-Mormugao Parliamentary Constituency held in March, 1977, has failed to lodge an account of his election as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pavaskar Ratnakant Ramchandra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. GOA-HP/2/77]

I. K. K. MENON, Secy.

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1977

आयकर

का० आ० 3886.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि रोज फाउण्डेशन, मुम्बई को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii) के अधीन अधिसूचना सं० 86 (फा० सं० 203/26/71-आई० टी० ए०-II) द्वारा 10-5-1972 से दिया गया अनुमोदन विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय बिक्री अनुसंधान

परिषद् नई दिल्ली की सिफारिश पर 21-3-1977 से वापस लिया जाता है।

[स० 1945/फा० सं० 203/42/77-आई० टी० ए० II]

जे० पी० शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th August, 1977

INCOME-TAX

S.O. 3886.—It is hereby notified for general information that the approval given under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to the Rose Foundation, Bombay by notification No. 86 (F. No. 203/26/71-ITA, II) with effect from 10-5-1972 is withdrawn with effect from 21-3-1977 on the recommendation of the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi.

[No. 1945/F. No. 203/42/77-ITA, II]

J. P. SHARMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1977

सीमा-शुल्क

का० आ० 3887.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 62) की धारा 7 के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 67-सीमा-शुल्क तारीख 20 मई, 1972 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

—उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3
"2.	जयनगर	भारत में जयनगर और नेपाल में जनकपुर को जोड़ने वाली रेल पटरी तथा भारत में जयनगर और नेपाल में चन्द्रगंज को जोड़ने वाला सड़क मार्ग।"

[स० 249 फा० सं० 652/128-एम०/77-एल० सी० आई०]

एन० कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd December, 1977

CUSTOMS

S.O. 3887. In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 67-Customs, dated the 20th May, 1972, namely :—

In the Table appended to the said notification, for Serial No. 2 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

1.	2	3
"2.	Jaynagar Railway line connecting Jayanagar in India and Janakpur in Nepal and road route connecting Jayanagar in India and Chandraganj in Nepal".	

[No. 249/F. No. 552/128-M/77-L.C. I]

N. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1977

आय-कर

का० आ० 3888.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "थिरुवावाडुथुराई अधिनियम" को निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए और उसे उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 1959/फा० सं० 197/179/76-आ० क० (ए०)]

New Delhi, the 5th September, 1977

INCOME-TAX

S.O. 3888.—In exercise of the powers conferred by Clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Thiruvavaduthurai Adheenam' for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1972-73

[No. 1959/F. No. 197/179/76-IT(AI)]

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1977

फा० आ० 3889.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं० 1610 तारीख 31-12-76 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

"निर्धारण वर्ष 1975-76" शब्दों और अंकों के स्थान पर

"निर्धारण वर्ष 1971-72" शब्द और अंक पढ़ें।

[सं० 1982/फा० सं० 197/103/77-आ० क० (ए०-I)]

New Delhi, the 20th September, 1977

INCOME-TAX

S.O. 3889.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby amends its Notification No. 1610 dated 31-12-1976 as below:—

For the words "assessment year 1975-76"

Read "assessment year 1971-72".

[No. 1982/ F. No. 197/103/77-IT(AI)]

आय-कर

फा० आ० 3890.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री इकाम्बरनाथार टेम्पल काञ्चीपुरम-3" को निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए और उसे उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 1991/फा० सं० 197/67/77-आ० क० (ए०-I)]

INCOME-TAX

S.O. 3890.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Ekamparanathar Temple, Kancheepuram-3" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1971-72.

[No. 1991/F. No. 197/67/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1977

आय-कर

फा० आ० 3891.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री अरुलमीगु कोट्टई मारियम्मन कोट्टे

डिन्डीगुल जिला मुदुरई" को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 2014/फा० सं० 176/97/77-आई० (टी०-ए० I)]

एम० शास्त्री, प्रवर सचिव

New Delhi, the 17th October, 1977

INCOME-TAX

S.O. 3891.—In exercise of the powers conferred by section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmigu Kottai Mariamman Koil, Dindigul, Madurai Distt." to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Section.

[No. 2014/F. No. 176/97/77-IT/(AI)]

(बीमा स्कंध)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1977

फा० आ० 3892.—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती उषा एच० मेहता और श्री एन० सी० कृष्णन् को 15 अक्टूबर, 1978 तक के लिए क्रमशः श्रीमती हेमिन्दर कौर और श्री आर० वैकटेशन के स्थान पर एतद्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड का निदेशक नियुक्त करती है।

[फाइल संख्या 81(9)-इंश्योरेंस II/76]

डी० के० सिंह, निदेशक

(Insurance Wing)

New Delhi, the 2nd Dec., 1977

S.O. 3892.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Act 1956 (31 of 1956) the Central Government hereby appoint Smt. Usha H. Mehta and Shri N. C. Krishnan as Directors on the Board of the Life Insurance Corporation of India upto 15-10-1978 Vice Smt. Heminder Kaur and Shri R. Venkatesan respectively.

[File No. 81(9)-Ins. II/76]

D. K. SINGH, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1977

फा० आ० 2893.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 31 मार्च 1978 तक पूर्णचरमा विलामस बैंक लि० त्रिवुनीपुर पर केरल राज्य के त्रिचूर जिले में उसके द्वारा धृत कल्लेतुकरा गांव में अञ्चल सम्मति अर्थात् सर्वेक्षण नं० 176 और 177 के संबंध में लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15(17)-बी० प्रो० III/77]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 30th November, 1977

S.O. 3893.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the

Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply upto 31st March, 1978 to the Poornathrayeesa Vilasom Bank Ltd., Tripunithura, in respect of the immovable property, viz., survey nos. 176 and 177 at Kallettumkara village in Trichur District in Kerala State.

[No. 15(17)-B.O. III/77]

का० आ० 3894.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 22 दिसम्बर, 1978 तक गणेश बैंक प्रा. लि. कुर्ण्डवाड, पि. कुर्ण्डवाड पर कुर्ण्डवाड में उसके द्वारा धृत सर्वेक्षण नं० 2437, 2413 से 2446 और 2449 के भूमि खण्डों के विषय में लागू नहीं होंगे।

[सं० 15(27)-बी० प्रो० III/77]

S.O. 3894.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply upto 22nd December, 1978 to the Ganesh Bank of Kurundwad Ltd., Kurundwad, in respect of the plot of land bearing survey Nos. 2437, 2443 to 2446 and 2449 held by it at Kurundwad.

[No. 15(27)-B.O. III/77]

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1977

का० आ० 3895.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 5 अक्टूबर, 1978 तक विजया बैंक लि०, मंगलूर पर मंगलूर (माऊथ कनारा) में उसके द्वारा धृत भूचल सम्पत्ति (टी० एम० संख्या 832 का भूमि खण्ड) के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15(6) बी० प्रो० III/77]

से० आ० उमगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 1st December, 1977

S.O. 3895.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply upto 5th October 1978 to the Vijaya Bank Ltd., Mangalore in respect of the immovable property (plot of land bearing T.S. No. 832) held by it at Mangalore (South Kanara).

[No. 15(6)-B.O. III/77]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली 30 नवम्बर, 1977

का० आ० 3896.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (य ख) के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा बिब्रूगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिब्रूगढ़, जिला बिब्रूगढ़ (असम) विषयक भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के 18 अक्टूबर, 1977 के स्थान आदेश संख्या एक-8-17/77 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में अंकों, वर्णों और शब्दों "30 नवम्बर, 1977" के स्थान पर अंक, वर्ण और शब्द "23 अप्रैल, 1978" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या एक-8-17/77-ए सी]

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1977

S.O. 3896. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 read with clause (zb) of Section 56 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of moratorium of the Government of India in the Department of Economic Affairs, (Banking Division) No. F. 8-17/77-AC dated 18th October, 1977 in the respect of the Dibrugarh Central Cooperative Bank Ltd., Dibrugarh, Dibrugarh District (Assam) namely :—

In the said Order, for the figures, letters and words "30th November, 1977" the figures, letters and words "23rd April, 1978" shall be substituted.

[No. F. 8-17/77-AC]

आदेश

का० आ० 3897.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (य ख) के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा तेजपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तेजपुर, जिला दारंग (असम) विषयक भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के 18 अक्टूबर, 1977 के स्थान आदेश संख्या एक-8-17/77 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में अंकों, वर्णों और शब्दों "30 नवम्बर, 1977" के स्थान पर अंक, वर्ण और शब्द "23 अप्रैल, 1978" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या एक-8-17/77-ए सी]

ORDER

S.O. 3897.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 read with clause (zb) of Section 56 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of moratorium of the Government of India in the Department of Economic Affairs, (Banking Division) No. F. 8-17/77-AC dated 18th October, 1977 in the respect of the Tezpur Central Cooperative Bank Ltd., Tezpur, Darrang District (Assam), namely :—

In the said Order, for the figures, letters and words "30th November, 1977" the figures, letters and words "23rd April, 1978" shall be substituted.

[No. F. 8-17/77-AC]

आदेश

का० आ० 3898.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (य ख) के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा गोपलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दूबरी, जिला गोपालपाड़ा (असम) विषयक भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के 18 अक्टूबर, 1977 के स्थान आदेश संख्या एक० 8-17/77-ए सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में अंकों, वर्णों और शब्दों "30 नवम्बर, 1977" के स्थान पर अंक, वर्ण और शब्द "23 अप्रैल, 1978" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

संख्या एक-8-17/77-ए सी]

ORDER

S.O. 3898.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 read with clause (zb) of Section 56 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of moratorium of the Government of India in the Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 8-17/77-AC dated 18th October, 1977 in the respect of the Goalpara District Central Cooperative Bank Ltd., Dhubri, Goalpara District (Assam), namely:—

In the said Order, for the figures, letters and words "30th November, 1977" the figures, letters and words "23rd April, 1978" shall be substituted.

[No. F. 8-17/77-AC]

आदेश

क्र० आ० 3898.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (यख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नौगांव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला नौगांव (असम) विषयक भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के 18 अक्टूबर, 1977 के स्थगन आदेश संख्या एफ० 8-17/77 ए सी में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:—

उक्त आदेश में अंकों, वर्णों और शब्दों "30 नवम्बर, 1977" के स्थान पर अंक, वर्ण और शब्द "23 अप्रैल, 1978" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या एफ 8-17/77 ए० सी०]

ORDER

S.O. 3899.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 read with clause (zb) of Section 56 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of moratorium of the Government of India in the Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 8-17/77-AC dated 18th October, 1977 in the respect of the Nowgong Central Cooperative Bank Ltd., Nowgong District, (Assam) namely:—

In the said Order, for the figures, letters and words "30th November, 1977" the figures, letters and words "23rd April, 1978" shall be substituted.

[No. F. 8-17/77-AC]

आदेश

क्र० आ० 3900.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (यख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा कछार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिलचर, जिला कछार (असम) विषयक भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के 18 अक्टूबर, 1977 के स्थगन आदेश संख्या एफ० 8-17/77 ए सी में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:—

उक्त आदेश में अंकों, वर्णों और शब्दों "30 नवम्बर, 1977" के स्थान पर अंक, वर्ण और शब्द "23 अप्रैल, 1978" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या एफ० 8-17/77-ए सी०]

ORDER

S.O. 3900.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 read with clause (zb) of Section 56 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of moratorium of the Government of India in the Department of Economic Affairs (Banking Division)

No. F. 8-17/77-AC dated 18th October, 1977 in the respect of the Cachar Central Cooperative Bank Ltd., Silchar, Cachar District (Assam) namely:—

In the said Order, for the figures, letters and words "30th November, 1977" the figures, letters and words "23rd April, 1978" shall be substituted.

[No. F. 8-17/77-AC]

आदेश

क्र० आ० 3901.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (यख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा कामरूप जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गौहाटी (असम) विषयक भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के 18 अक्टूबर, 1977 के स्थगन आदेश संख्या एफ० 8-17/77 ए सी में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:—

उक्त आदेश में अंकों, वर्णों और शब्दों "30 नवम्बर, 1977" के स्थान पर अंक, वर्ण और शब्द "23 अप्रैल, 1978" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या एफ० 8-17/77-ए सी०]

लोकेन्द्र नाथ शर्मा, अवर सचिव

ORDER

S.O. 3901.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 read with clause (zb) of Section 56 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of moratorium of the Government of India in the Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 8-17/77-AC dated 18th October, 1977 in the respect of the Kamrup District Central Cooperative Bank Ltd., Gauhati, (Assam), namely:—

In the said Order, for the figures, letters and words "30th November, 1977" the figures, letters and words "23rd April, 1978" shall be substituted.

[No. F. 8-17/77-AC]

L. N. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1977

क्र० आ० 3902.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 के खण्ड के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्वारा नवम्बर, 1977 के चौथे दिन से प्रारम्भ होकर नवम्बर, 1980 के तीसरे दिन की समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिये, उक्त खण्ड 3 के उपखण्ड (ग), (घ), (ङ) और (च) में निविष्ट व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) को दिनांक 7 फरवरी, 1974 की अधिसूचना संख्या एफ० 9-4/49/73-बी० प्र० 1-3 के अधीन नियुक्त निवेशकों के स्थान पर, पंजाब नेशनल बैंक के निवेशकों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:—

1. डा० ए० एस० कहलन, उक्त बैंक के जमाकर्ताओं के हितों कीन, कालेज आफ बेनिक साइंसेस का प्रतिनिधित्व करने के लिये एण्ड ह्यूमेनिट्रीज, खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) के पंजाब कृषि विश्व विद्यालय अनुसरण में। सुधियाना (पंजाब)
2. त्रिगेवियर घासी राम (सेदा किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व निवृत्त) नवियां फार्म, भरतपुर करने के लिये खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में। (राजस्थान)

3. श्री जी० रसूल खां, कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व निदेशक, करने के लिए खण्ड 3 के उप-खण्ड (ड) के अनुसरण में।
गुलाम मोहिदीन एण्ड सन्स प्राइ-
वेट लिमिटेड,
रेसीडेंसी रोड, श्रीनगर (जम्मू
और कश्मीर)
4. श्री बृजमोहन लाल, खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनु-
प्रबन्ध निदेशक, सरण में।
हीरो साइकल प्राइवेट लिमिटेड,
हीरो नगर, जी० टी० रोड,
लुधियाना (पंजाब)
5. श्री रिछ पाल मेहरा, खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनु-
बी० ए० (आनर्स), एल० एम० श्री० सरण में।
621, रविदाम नगर,
रोहतास (हरियाणा)
6. श्रीमती रामोला नन्दी, खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनु-
शिक्षा-शास्त्री और सामाजिक सरण में।
कार्यकर्ता,
"श्याम श्री" म्यूजियम रोड,
पटना (बिहार)
7. श्री रोमेश्वर ठाकुर, खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनु-
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, सरण में।
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी,
124, जानपथ,
नई दिल्ली-110001

[सं० एफ० 9/23/77 श्री० श्री० I]
बलदेव सिंह, सचिव

New Delhi, the 4th November, 1977

S.O. 3902.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons as Directors of the Punjab National Bank for a period of three years commencing on the 4th day of November, 1977 and ending with the 3rd day of November, 1980, in the place of the Directors appointed under the notification of the Government

of India in the Ministry of Finance (Department of Banking No. F. 9-4/49/73 BO, I-3, dated the 7th February, 1974 to represent the interests of the persons specified in sub-clauses (d) (e) and (f) of the said clause 3 :

1. Dr. A.S. Kahlon, Dean, Representing the interests of College of Basic Sciences & depositors of the said Humanities, Punjab Agri- Bank in pursuance of sub-cultural University Ludhiana clause (d) of clause 3. (Punjab)
2. Brig. Ghazi Ram (Retd.) Representing the interests of Nadia Farm, Bharatpur farmers—in pursuance of (Rajasthan) sub-clause (e) of clause 3.
3. Shri G. Rusull Khan, Representing the interests of Director, Gulam Mohidin & artisans—in pursuance of Son Pvt Ltd., Residency sub-clause (e) of clause 3. Road, Srinagar, (Jammu & Kashmir)
4. Shri Brijmohan Lall, Mana- In pursuance of sub-clause ging Director, Hero Cycles (f) of clause 3, (Pvt) Ltd., Hero Nagar, G.T. Road, Ludhiana (Punjab)
5. Shri Rich Pal Mehra In pursuance of sub-clause (f) B.A. (Hons.) LLB. 621, Ravi of clause 3. Dass Nagar Rohtak, (Haryana)
6. Mrs. Ramola Nandi, Educa- In pursuance of sub-clause (f) tionist and Social Worker of clause 3. "Shyam Shree" Museum Road Patna. (Bihar)
7. Shri Rameshwar Thakur, In pursuance of sub-clause (f) Chartered Accountant, of clause 3. Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co 124, Janpath, New Delhi 110001.

[No. F-9/23/77-B.O.I]
BALDEV SINGH, Jt. Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

आय-कर

क्र० आ० 3903.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं० 1718 (फा० सं० 188/4/77-आई टी/ए-1) तारीख 11-4-1977 में उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।
उक्त अनुसूची में, क्रम संख्या 84 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा।

1	2	3	4	5	6
क्रम सं०	ऐसे सभी व्यक्ति, जिनकी बाबत (तस्करी और विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के लिए) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम और/या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध का आदेश किया गया है और जो उक्त अधिनियमों के अधीन आदेश पारित किए जाने से पूर्व गुजरात राज्य के अहमदाबाद, गांधीनगर, कैरा, मेहसाना, बनसकाठा और सबरकांठा राजस्व जिलों के भीतर निवास करने थे या कारबार या व्यवसाय करते थे और जिनके मामले आयकर अधिनियम की धारा 127 के अधीन अहमदाबाद के केन्द्रीय सर्किल को, या अहमदाबाद, जामनगर, और सूरत के विशेष अन्वेषण सर्किलों के किसी भी आयकर अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं।	आयकर अधिकारी, विशेष अन्वेषण सर्किल-I अहमदाबाद	आयकर आयुक्त (अपील) ए० आर० 8 अहमदाबाद जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 3 में वर्णित सर्किल पर है।	सहायक आयुक्त (अपील) ए० आर० 6 अहमदाबाद जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 3 में वर्णित सर्किल पर है।	आयकर आयुक्त गुजरात-1 जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 3 में वर्णित सर्किल पर है।
84 (i)					
(ii)	ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी बाबत (तस्करी और विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के लिए) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम और/या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के अधीन निरोध का आदेश किया गया है और जो उक्त अधिनियमों के अधीन आदेश पारित किए जाने से पूर्व गुजरात राज्य के पंचमहल, वडोदा, बड़ोच, सूरत, डांगा, और बूलसर के राजस्व जिलों और दमन, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करने थे या कारबार या व्यवसाय करते थे और जिनके मामले आयकर अधिनियम की धारा 127 के अधीन अहमदाबाद के केन्द्रीय सर्किल को, या अहमदाबाद, जामनगर और सूरत के विशेष अन्वेषण सर्किलों के किसी भी आयकर अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं।	आयकर अधिकारी विशेष अन्वेषण सर्किल 1 सूरत	आयकर आयुक्त (अपील) ए० आर० 8 अहमदाबाद जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 3 में वर्णित सर्किल पर है।	आयकर आयुक्त (अपील) ए० आर० 8 अहमदाबाद जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 3 में वर्णित सर्किल पर है।	आयकर आयुक्त गुजरात 1 जिसकी अधिकारिता स्तम्भ-3 में वर्णित सर्किल पर है।
(iii)	ऐसे सभी व्यक्ति, जिनकी बाबत (तस्करी और विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के लिए) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिनियम और/या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध का आदेश किया गया है और जो उक्त अधिनियमों के अधीन आदेश पारित किए जाने से पूर्व गुजरात राज्य के राजकोट, जूनागढ़, मुरेन्द्रगढ़, भावनगर, अमरेली, जामनगर और कच्छ के राजस्व जिलों और दीव संघ राज्य क्षेत्र में निवास करने थे या कारबार या व्यवसाय करते थे और जिनके मामले आयकर अधिनियम की धारा 127 के अधीन अहमदाबाद के केन्द्रीय सर्किल, अहमदाबाद, जामनगर, और सूरत के विशेष अन्वेषण सर्किलों के किसी भी आयकर अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं।	आयकर अधिकारी विशेष अन्वेषण सर्किल जामनगर	आयकर आयुक्त (अपील) ए० आर० 8 अहमदाबाद जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 3 में वर्णित सर्किल पर है।	आयकर आयुक्त (अपील), जे० आर० जामनगर जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 3 में वर्णित सर्किल पर है।	आयकर आयुक्त गुजरात 1, जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 2 में वर्णित सर्किल पर है।

2 यह अधिसूचना 1-4-76 से प्रभावी है।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

* New Delhi, the 1st September, 1977

INCOME-TAX

S.O. 3903.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule annexed to its Notification No. 1718/(F. No. 188/4/77-IT(AI)) dated 11-4-1977 In the said Schedule at Sl. No. 84 the following shall be substituted.

1	2	3	4	5	6	
Sl. No.		I.T.O.	SIC-I A	I.A.C.A.R. VIII	A.A.C.A.R. VI. A	C.I.T. Gujarat-I
84 (i)	All persons in respect of whom an order of detention has been made under the Maintenance of Internal Security Act (for smuggling activities and foreign exchange racketeering) and/or Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and who prior to passing of orders under the said Acts were residing or carrying on business or profession within the Revenue Districts of Ahmedabad, Gandhinagar, Kalra, Mehsana, Banaskantha and Sabarkantha of the State of Gujarat and whose cases are not assigned to any of the I.T.Os. in Central Circles, Ahmedabad and Special Investigation Circles, Ahmedabad, Jamnagar and Surat by an order u/s. 127 of the I.T. Act.	'bad'		A 'bad' who has jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.	'bad' who has got jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.	who has got jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.
(ii)	All persons in respect of whom an order of detention has been made under the Maintenance of Internal Security Act (for smuggling activities and foreign exchanges racketeering) and/or Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and who prior to passing of orders under the said Acts were residing or carrying on business or profession within the Revenue Districts of Panchmahal, Baroda, Broach, Surat, Danga and Bulsar of the State of Gujarat and in the Union Territory of Daman, Dadra and Nagar Haveli and whose case are not assigned to any of the I.T.Os in Central Circles, Ahmedabad and Special Investigation Circles, Ahmedabad, Jamnagar and Surat by an order u/s. 127 of the I.T. Act.	I.T.O. S.I.C. I Surat.		I.A.C.A.R. VIII A 'bad' who has jurisdiction over the circle mentioned in Col. 3.	A.A.C.S.R. Surat who has got jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.	C.I.T. Gujarat-I who has got jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.
(iii)	All persons in respect of whom an order of detention has been made under the Maintenance of Internal Security Act (for smuggling activities and foreign Exchange Racketeering) and/or Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and who prior to passing of orders under the said Acts were residing or carrying on business or profession within the Revenue Districts of Rajkot, Junagadh, Surendranagar, Bhavnagar, Amreli, Jamnagar and Kutch of the State of Gujarat and in the Union Territory of Diu and whose cases are not assigned to any of the I.T.Os in Central Circles, Ahmedabad and Special Investigation Circles, Ahmedabad, Jamnagar and Surat by an order u/s. 127 of the Income-tax Act.	I.T.O. S.I.C. Jamnagar.		I.A.C. A.R. VIII A 'bad' who has jurisdiction over the circle mentioned in Col. 3.	A.A.C.J.R. Jamnagar who has got jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.	C.I.T. Gujarat-I who has got jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.

2. This Notification shall have effect from 1-9-1977.

[No. 1948/F.No. 188/4/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1977

आय-कर

क्रा० अा० 3904.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63 आ० क०), तारीख 18 मई, 1964, से उपाखण्ड अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

उक्त अनुसूची में क्रम सं० 44 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

1	2	3	4	5	6
"44.	उपनिर्देशक सैनिक लेखा जामनगर के लेखापरीक्षा नियंत्रण के अधीन रखा सेवा कर्मचारी	आय-कर अधिकारी (सहायक) (विदेश जामनगर अनुभाग)	सहायक निरीक्षण आयुक्त आय-कर रेंज, जामनगर	सहायक आय-कर (अपील) जामनगर रेंज, जामनगर	आय-कर आयुक्त गुजरात-5 अहमदाबाद"

[सं० 1968/फा० सं० 188/2/77-आई० टी० (ए 1)]

New Delhi, the 14th September, 1977

INCOME-TAX

S.O. 3904.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule annexed to its Notification No.1 (F. No. 55/233/63-IT) dated the 18th May, 1964, as amended from time to time.

For the existing entries appearing against Serial No. 44 in the said Schedule, the following shall be substituted.

1	2	3	4	5	6
"44.	Defence Services Employees under the Audit Control of the Deputy Controller of Military Accounts, Jamnagar.	Income-tax Officer, Ward-F, (Asstt) Jamnagar, (Foreign section).	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Jamnagar Range, Jamnagar.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Jamnagar Range, Jamnagar.	Commissioner of Income-tax, Gujarat-V, Ahmedabad."

[No. 1968/F. No.188/2/77-II(AI)]

New Delhi, the 20th September, 1977

आय-कर

INCOME-TAX

क्रा०अा० 3905.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 1090 (फा० सं० 187/2/74-आई टी (ए I) तारीख 20-9-1975 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

क्रम सं० 23 के सामने स्तम्भ 1, 2 और 3 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
"23 व पश्चिमी बंगाल-V	कलकत्ता	1. जूट सर्किल, कलकत्ता 2. कम्पनी जिला V कलकत्ता 3. सहकारिता सर्किल कलकत्ता 4. विदेशी कम्पनी सर्किल I कलकत्ता 5. विदेशी कम्पनी सर्किल II कलकत्ता 6. विशेष अन्वेषण सर्किल I कलकत्ता"

यह अधिसूचना 26-9-1977 से प्रभावी होगी।

[सं० 1992/फा० सं० 187/4/77-आई टी (ए I)]

S.O. 3905.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Notification No. 1090/F. No. 187/2/74-IT(AI) dated 20-9-1975 as amended from time to time.

The entries under columns 1, 2 and 3 against Sl. No. 23 D shall be substituted by the following entries.

Commissioner of Income-tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3
"23D West Bengal-V	Calcutta	1. Jute Circle, Calcutta. 2. Comp. Dist. V. Calcutta. 3. Co-operative Circle, Calcutta. 4. Foreign Companies Circle-I, Calcutta. 5. Foreign Companies Circle-II, Calcutta. 6. Special Investigation Circle-I, Calcutta."

This notification shall take effect from 26-9-1977.

[No. 1992/F. No. 187/4/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1977

आय-कर

क्र०आ० 3906.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सं० 679/फा० सं० 137/2/74-आई टी (ए 1) तारीख 20-7-1974 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

क्रम सं० 4 और 4क के सामने क्रम सं 1, 2 और 3 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी :

अनुसूची

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
4. आय-कर आयुक्त, बिहार-I	पटना	1. संपदा शुल्क एवं आयकर सफिल, पटना 2. आय-कर सफिल-I पटना 3. आय-कर सफिल-II, पटना 4. आय-कर सफिल-III, पटना 5. विशेष सफिल-I, पटना 6. विशेष सफिल-II, पटना 7. आय-कर सफिल, बिहार शरीफ 8. आय-कर सफिल, धारा 9. आय-कर सफिल, भागलपुर 10. आय-कर सफिल, मुंगेर 11. आय-कर सफिल, मुजफ्फरपुर 12. आय-कर सफिल, छपरा 13. आय-कर सफिल, दरभंगा 14. आय-कर सफिल, सहरसा 15. आय-कर सफिल, पूर्णिया 16. आय-कर सफिल, बेतिया 17. आय-कर सफिल, मोतीहारी 18. आय-कर सफिल, बेगूसराय 19. आय-कर सफिल, सासाराम 20. आय-कर सफिल, देवगढ़
4क. आयकर आयुक्त बिहार-II	पटना	1. संपदाशुल्क एवं आय-कर सफिल, रांची 2. आय-कर सफिल, रांची 3. विशेष सफिल, रांची 4. आय-कर सफिल, जमशेदपुर 5. विशेष सफिल, जमशेदपुर 6. वेतन सफिल, जमशेदपुर 7. आय-कर सफिल-I, डाल्टनगंज 8. आय-कर सफिल-I, धनबाद 9. आय-कर सफिल, धनबाद 10. विशेष सफिल, धनबाद 11. आय-कर सफिल, बोकारो 12. आय-कर सफिल, हजारीबाग 13. आय-कर सफिल, गिरीडीह 14. आय-कर सफिल, गया

यह अधिसूचना 15-10-1977 से प्रभावी होगी।

[सं० 2008/फा० सं० 187/19/77-आई टी (ए 1)]

New Delhi, the 13th October, 1977

INCOME-TAX

S.O. 3906.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule appended to the Notification No. 679/F. No. 187/2/74-IT-(AI) dated 20-7-1974 as amended from time to time.

Existing entries under Columns 1, 2 and 3 against Serial Nos. 4 and 4A in the Schedule shall be substituted by the following entries :—

SCHEDULE

Commissioner of Income Tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3
4. Commissioner of Income-tax, Bihar-I	Patna	1. Estate-Duty-Cum-Income-tax Circle, Patna. 2. I.T. Circle-I, Patna. 3. I.T. Circle-II, Patna. 4. I.T. Circle-III, Patna. 5. Special Circle-I, Patna. 6. Special Circle-II, Patna. 7. I.T. Circle, Bihar-sharif. 8. I.T. Circle, Arrah. 9. I.T. Circle, Bhagalpur. 10. I.T. Circle, Monghyr. 11. I.T. Circle, Muzaffarpur. 12. I.T. Circle, Chapra. 13. I.T. Circle, Darbhanga. 14. I.T. Circle, Saharsa. 15. I.T. Circle, Purnea. 16. I.T. Circle, Bettiah. 17. I.T. Circle, Motihar. 18. I.T. Circle, Begusarai. 19. I.T. Circle, Sasaram. 20. I.T. Circle, Deoghar.
4A. Commissioner of Income-tax, Bihar-II	Patna	1. Estate Duty-Cum-Income-tax Circle, Ranchi. 2. I.T. Circle, Ranchi. 3. Special Circle, Ranchi. 4. I.T. Circle, Jamshedpur. 5. Special Circle, Jamshedpur. 6. Salary Circle, Jamshedpur. 7. I.T. Circle, Daltonganj.

1	2	3
		8. I.T. Circle-I, Dhanbad.
		9. I.T. Circle-II, Dhanbad.
		10. Special Circle, Dhanbad.
		11. I.T. Circle, Bokaro.
		12. I.T. Circle, Hazaribagh.
		13. I.T. Circle, Giridih.
		14. I.T. Circle, Gaya.

This Notification shall have effect from 15-10-1977.

[No. 2008/F. No. 187/19/77-IT(AI)]

सूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1977

आय-कर

कां.आ. 3907.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई बोर्ड की अधिसूचना सं. 1992 तारीख 20-9-77 [फा. सं. 187/4/77 आई टी (ए 1)] में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

“यह अधिसूचना 26-9-1977 से प्रभावी होगी” के स्थान पर

“यह अधिसूचना 1-9-77 से प्रभावी होगी” पढ़ें।

[सं. 2011/फा. सं. 187/4/77 आई टी (ए 1)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th October, 1977

INCOME-TAX

S. O. 3907.—In the Board's notification No. 1992 dated 20-9-1977 [F. No. 187/4/77-IT(AI)] issued under sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), following amendment shall be made.

For “This Notification shall take effect from 26-9-1977.”
Read “This Notification shall take effect from 1-9-1977.”

[No. 2011/F. No. 187/4/77-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

उप-मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात का कार्यालय, बंगलौर

आदेश

बंगलौर, 24 अगस्त, 1977

कां.आ. 3908.—सर्वश्री जिव्दल एल्यूमिनियम लि., 16वां कि०मी० टुमकुर रोड, बंगलौर-562139 को 1.89 लाख रुपये तक सीमनिशियम मेटल और एनोडाइसिंग रजक के आयात के लिए 3,39,059 रुपये का एक आयात लाइसेंस संख्या पी/एल/2737827/सी/एक्स एक्स/61/एक्स/

43-44/ए.66.1 ए.66.2 दिनांक 4-11-1976 प्रदान किया गया था। उन्होंने अब उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति 1,89,059 रुपये मात्र तक उपयोग ? लाने के पश्चात् आवागमन में खो गई है और अब उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति शेष धन 1.5 लाख रुपये के मूल्य के लिए आवश्यक है।

उपर्युक्त तर्कों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए। उक्त लाइसेंस की मूल प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या ए०-7/जे०एस० 76/भार०ई०पी०/बंग]

भार० जयराम नायडू, उप-मुख्य निर्यातक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Bangalore)

ORDER

Bangalore, the 24th August, 1977

S.O. 3908.—M/s. Jindal Aluminium Ltd., 16th K. M. Tumkur Road, Bangalore-562139, were granted an import licence No. P/L/2737827/C/XXI/61/X/43-44/A.66.1A.66.2 dated 4-11-76 for Rs. 3,39,059 for import of Magnesium Metal upto Rs. 1.89 lakhs and Anodising Dyes. They have now applied for duplicate copy of Exchange Control Purpose Copy of the above licence on the ground that the original of the Exchange Control Purposes copy of the licence has been lost in transit after utilising it for Rs. 1,89,059 only, and that the duplicate copy of the above licence now required is for the balance value of Rs. 1.5 lakhs.

In support of the above contention, the applicant has filed an Affidavit. I am satisfied that the original Exchange Control Purpose Copy of the above licence has been lost and direct that a duplicate copy of Exchange Control Purpose copy of the licence should be issued to the applicant. The Original copy of the above licence is hereby cancelled.

[No. A. 7/J.S. 76/REP/Bang]

R. JAYARAM NAIDU, Dy. Chief Controller

मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1977

कां.आ. 3909.—सर्वश्री क्लार्क टेक्स्टाइल इन्डस्ट्रिज, 11/13 बोटवाला बिल्डिंग होरीयेन सफिल, फोर्ट बम्बई को लाइसेंस के साथ संलग्न सूची के अनुसार कच्चे माल का आयात करने के लिए 27,000 रुपये के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/बी/2420974, दिनांक 8-9-76 प्रदान किया गया था।

2. अब फर्म ने आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमा शुल्क प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस की दोनों प्रतियां सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल उपयोग में लाए बिना ही खो गई हैं।

3. अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण ऐड बुक नियम एवं क्रियाविधि 1977 के पैरा 320 में यथा अपेक्षित, एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात

लाइसेंस संख्या पी/सी/2420974, दिनांक 8-9-1976 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमा शुल्क प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं और निदेश देता है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमा शुल्क प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां आवेदक को जारी की जानी चाहिए। यदि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमा शुल्क प्रयोजन प्रतियां यदि मिल गईं तो उन्हें रद्द करने के लिए इस कार्यालय को भेज दी जाएगी।

4. आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमा शुल्क प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[संख्या आई एम/सी-2(1)/ए एम-76/आर०एम०-7/400]

राजिन्दर सिंह, उप-मुख्य नियंत्रक

Office of the Chief Controller of Imports & Exports,
New Delhi

ORDER

New Delhi, the 26th October, 1977

S.O. 3909.—M/s. Climax Textile Engravers, 11/13 Botawala Building, Horiman Circle, Fort Bombay were granted import licence No. P/D/2420974 dated 8-9-76 for Rs. 27,000 for the import of Raw Material as per list attached with the licence.

2. The firm have now requested for the issue of duplicate copies of Exchange Control and Customs Purposes copies of the import licence on the ground that both the copies of the original licence have been lost without having been registered with the Customs authority and utilised at all.

3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit, as required in para 320 of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control & Customs Purposes copies of the import licence No. P/D/2420974 dated 8-9-1976 have been lost and directs that duplicate copies of Exchange Control and Customs Purposes copies of the licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control and Customs Purposes copies of the licence, if found, will be forwarded to this office for cancellation.

4. The Duplicate copies of Exchange Control & Customs Purposes copies of the import licence are being issued separately.

[File No. IM/C-2(1)/AM-76/RM-7/400]

RAJINDER SINGH, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1977

का०आ० 3910.—भारत का उर्वरक निगम लि० नई दिल्ली को आई०ई०ए० देशों से ट्रांस्फे एकक के लिए पूंजीगत उपकरण के फालतू पुर्जों के आयात के लिए 45,00,000 रुपये (पैंतालीस लाख रुपये मात्र) का आयात लाइसेंस सं०आई/सी/2070559/सी/आई ए/57/एच/41-42/सीजी-2/एल०एस०, दिनांक 27-11-1975 प्रदान किया गया था। भारत के उर्वरक निगम लि० ने आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है। इसके समर्थन में, भारत के उर्वरक निगम लि० ने मोटरी पब्लिक बम्बई के सामने विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस बात की पुष्टि कर ली गई है कि उपर्युक्त लाइसेंस सीमा शुल्क कार्यालय बम्बई के पास पंजीकृत कराने के पश्चात् खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। मैं संतुष्ट हूँ कि मूल आयात लाइसेंस संख्या आई/सी/2070559/सी/आई ए/57/एच/41-42/सीजी-2/एल०एस० की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और 39,37,336 रुपये की सीमा तक उसका उपयोग कर लिया गया है,

जिसमें शेष अप्रयुक्त 5,62,662 रुपये मात्र हैं और निदेश देता हूँ कि उपर्युक्त आयात लाइसेंस संख्या आई/सी/2070559/सी/आई ए/57/एच/41-42/सीजी-2/एल०एस० दिनांक, 27-11-75 की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए।

[संख्या सीजी-2/पी एच सी/144-145/75-76/208]

टी० टी० ला, उप-मुख्य नियंत्रक,

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1977

S.O. 3910.—The Fertilizer Corporation of India Ltd., New Delhi were granted import licence No. I/C/2070559/C/IA/57/H/41-42/CGII/L.S. dated 27-11-75 for Rs. 45,00,000 (Rupees Forty five lakhs only) for the import of spares for Capital equipment for Trombay Unit from all I.D.A. Countries. The Fertilizer Corporation of India Ltd. have applied for issue of duplicate Customs Copy of the import licence. In support of this the Fertilizer Corporation of India Ltd. have furnished an affidavit on the stamped paper duly sworn before the Notary Public, Bombay. It is affirmed that the said licence was lost/misplaced after having been registered with Bombay custom house, I am satisfied that the original import licence No. I/C/2070559/C/IA/57/H/41-42/CGII/L.S. dated 27-11-75. Customs Purpose copy has been lost/misplaced and utilised to the extent of Rs. 39,37,336 having an unutilised balance of Rs. 5,62,664 only, and direct that duplicate copy of the said import licence No. I/C/2070559/C/IA/57/H/41-42/CGII/L.S., dated 27-11-1975. Customs purpose copy may be issued to the applicant.

[No. CGII/P&C/144-145/75-76/1380]

T. T. LA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1977

का०आ० 3911.—सर्वश्री पी० एच ई०सी० फाफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ से संलग्न सूची के अनुसार क्लोल्ड एथीकलथरल ट्रैक्टर के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए 14,64,000 रुपये मूल्य का लाइसेंस सं० जी/टी/2383489 दिनांक 14-11-69 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रति जारी करने के लिए इस प्राधिकार पर आवेदन किया है कि उनसे मूल सीमा-शुल्क प्रति खो गई है। लाइसेंसधारी ने प्रागे यह भी बताया है कि लाइसेंस मद्रास पवन पर पंजीकृत कराया गया था।

अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है और यह बताया है कि लाइसेंस का 45,178.80 रुपये के लिए उपयोग कर लिया गया था और अब शेष 14,18,821.20 रुपये के लिए अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० जी/टी/2383489 दिनांक 14-11-69 की सीमा-शुल्क प्रति खो गई है और निदेश देता है कि अप्रयुक्त शेष मूल्य 14,18,821.20 रुपये के लिए उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति उनको जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की सीमा-शुल्क निकासी प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

लाइसेंस सं० जी/टी/2383489 दिनांक 14-11-69 की सीमा-शुल्क निकासी प्रति अलग से जारी की जाती है।

[संख्या एस टी सी/यू एम एस आर-2-5/69-70/आर एम-VIII/917]

जी० एस० प्रेवाल, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 2nd December, 1977

S.O. 3911.—The P. & E. C. of India Ltd., New Delhi were granted licence No. G/T/2383489 dt. 14-11-69 for the

Import of Spares Parts for Wheeled Agricultural Tractor as per list attached from USSR to the value of Rs. 14,64,000/-. They have requested for the issue of duplicate Customs Copy of the above licence in the ground that the Original CC of the above licence has been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence has been registered with the port at Madras.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit and stated that the licence was utilised for Rs. 45,178.80/- and that the Duplicate only now required is to cover the balance of Rs. 14,18,821.20 P. The under-

signed is satisfied that C.C. of licence No. G/T/2383489 dt. 14-11-69 has been lost and direct that Custom Copy of the said licence for the unutilised balance of Rs. 14,18,821.20 P. should be issued to them. The C.C. of the licence is hereby cancelled.

C.C. of the licence No. G/T/2383489 dt. 14-11-69 is being issued separately.

[No. STC/USSR-2-5/69-70/RM-VIII/917]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller.

नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय



भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1977

का.प्र. 3912.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम 1955 के नियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किया है जिसकी डिजाइन शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानक के शीर्षक सहित अनुसूची में दी गई हैं।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिह्न उनके भागे दी तिथियों से लागू होंगे।

अनुसूची

क्रम मानक चिह्न की डिजाइन संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बन्धी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. IS : 4250 	बिजली की घरेलू मिस्त्रियों (ब्रव-कारी, मिश्रक और पेषक)	IS : 4250-1967 बिजली की घरेलू मिस्त्रियों (ब्रवकारी, मिश्रक और पेषक) की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1977-04-16
2. IS : 7586 	खानों में प्रयुक्त वर्षण बल टेक	IS : 7586-1975 खानों में प्रयुक्त वर्षण बल टेक की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1977-09-16

[सं० सी एम डी/13 : 9]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION



INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 24th November, 1977

S.O. 3912.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Acts, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1.	IS : 4250 	Domestic electric food-mixers (liquidizers, blenders and grinders)	IS : 4250-1967 Specification for domestic electric food-mixers (liquidizers, blenders and grinders)	The monogram of the Indian Standards Institution consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1977-04-16
2.	IS : 7586 	Friction props for mines	IS : 7586-1975 Specification for Friction props for mines	The monogram of the Indian Standards Institution consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1977-07-16

[No. CMD/13 : 9]

क्रा०भा० 3913—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (2) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की प्रति हकाई मुहर लगाने की फीम अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है और यह फीम प्रत्येक वस्तुओं के आगे दी गई तिथियों से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी संख्या	तत्संबन्धी मानक की संख्या और गीर्षक	हकाई	प्रति हकाई मुहर लगाने की फीम	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. बिजली की घरेलू मिस्सियां (द्रवकारी, मिश्रक और पेचक)	IS : 4250-1967 बिजली की घरेलू मिस्सियों (द्रवकारी, मिश्रक और पेचक) की विशिष्टि	एक मिस्सी एवं ग्राइन्डर	रु० 2.00	1977-04-16
2. खानों में प्रयुक्त घर्षण बल टेक	IS : 7586-1975 खानों में प्रयुक्त घर्षण बल टेक की विशिष्टि	एक लघु	रु० 1.00	1977-09-16

[(संख्या सी एस डी/13 : 10)]

बाई० एस० बेंकटेश्वरन, प्रपर महानिदेशक

S.O. 3913.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1.	Domestic electric food-mixers (liquidizers, blenders and grinders)	IS : 4250-1967 Specification for domestic electric food-mixers) liquidizers, blenders and grinders)	One Mixer-cum-grinder	Rs. 2.00	1977-04-16
2.	Friction props for mines	IS : 7586-1975 Specification for friction props for mines	One piece	Rs. 1.00	1977-09-16

[No. CMD/13 : 10]

Y. S. VENKATESWARAN, Additional Director General

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1977

क्र० अ० 3914.—केन्द्रीय सरकार, अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन कानपुर कामाचिटी एक्सचेंज लि०, कानपुर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर बायदा बाजार प्रायोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को अगली की अधिम संविदाओं के बारे में, 27 नवम्बर, 1977 से 26 नवम्बर, 1978 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की प्रतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रवृत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो बायदा बाजार प्रायोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[मिफिल सं० 12 (17)-आई०टी/77]

New Delhi, the 26th November, 1977

S.O. 3914.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Kanpur Commodity Exchange Ltd., Kanpur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 27th November, 1977 to the 26th November, 1978, both days inclusive, in respect of forward contracts in linseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12(17)-IT/77]

क्र० अ० 3915.—केन्द्रीय सरकार, अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सुरेन्द्रनगर काटन प्रायस एण्ड प्रायसलीड्स एसोसियेशन लि, सुरेन्द्रनगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर बायदा बाजार प्रायोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसियेशन को कपास की अधिम संविदाओं के बारे में 23 नवम्बर, 1977 से 22 नवम्बर, 1978 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की प्रतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रवृत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसियेशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो बायदा बाजार प्रायोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[क्र० सं० 12 (19)-आई०टी./77]

S.O. 3915.—The Central Government having considered, in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Surendranagar Cotton Oil and Oilseeds Association Ltd., Surendranagar, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said association for a further period of one year from the 23rd November, 1977 to the 22nd November, 1978 (both days inclusive), in respect of forward contracts in kapas.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(19)/IT/77]

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1977

क्र० अ० 3915.—केन्द्रीय सरकार, अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन लुधियाना ग्रेन एक्सचेंज लि०, लुधियाना द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर बायदा बाजार प्रायोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को विनोले की अधिम संविदाओं के बारे में 12 दिसम्बर, 1977 से 11 दिसम्बर, 1978 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की प्रतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रवृत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो बायदा बाजार प्रायोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[मिफिल सं० 12 (18)-आई०टी०/77]

की० श्रीनिवासन, उप सचिव

New Delhi, the 5th December, 1977

S.O. 3916.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of

1952) by the Ludhiana Grain Exchange Ltd., Ludhiana, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 12th December, 1977 to 11th December, 1978 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(18)-IT/77]
V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1977

का०आ० 3917.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 770, तारीख 19-2-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में सभी भागों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा।

अनुसूची

खोलका 10 पर फ्लेयर 6 प्वाइंट से डब्ल्यू. एच. आई. तक उपयोग के अधिकार का अर्जन करना

राज्य : गुजरात	जिला : अहमदाबाद	तालुका : धोलका			
गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टेयर	ए०आर०ई०	सेण्टीयर	
वोधा	234/पांकी	0	03	00	
	228	0	04	20	

[सं० 12016/11/76-प्रोडक्शन]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 21st November, 1977

S.O. 3917.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 770 dated 19-2-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land)

Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of R.O.U. for Flare Point to W.H.I. at Dholka-10
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dholka

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Vautha	234/Paiki	0	03	00
	228	0	04	20

[No. 12016/11/76-Prod.]

का० आ० 3918.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप सं० एस०डी०एफ० से सी०सी०एस० एवं सी०टी०एफ०सी० सीमासन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण तथा रख रखाव प्रभाग, मकरपुरा रोड, बबोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कृप नं० एम० डी० एफ० से जी० पी० एम० एवं सी० टी० एफ० सोभासन
तक पाइप लाइन बिछाना
राज्य : गुजरात जिला तथा तालुका : मेहसाणा

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	ए० आर० सेण्टी- ई०	य०
हेबुवा	88	0	00	84
	89	0	12	96
	94	0	13	56
पुनासन	117/क	0	11	88
	126	0	04	80
	127	0	12	24
	130	0	03	60

[सं० 12016/1/77-प्रोडक्शन]

S.O. 3918.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from well No. SDF, to GGS-cum-CTF Sobhasan in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Markarpura Road, Vadodara-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Laying Pipeline from Well No. SDF to GGS-Cum-CTF Sobhasan

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hebuva	88	0	00	84
	89	0	12	96
	94	0	13	56
Punasan	117/A	0	11	88
	126	0	04	80
	127	0	12	24
	130	0	03	60

[No. 12016/1/77-Prod.]

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1977

का०आ० 3919.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 3136 तारीख 26-9-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

118 GI/77-3

और यतः वक्ष्य प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाना है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संयंत्रों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा।

अनुसूची

जंकशन पाइंट से जी०पी०एम०-8 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कपोल

गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टेयर	ए० आर० सेण्टी- ई०	य०
कपोल	676/3	0	06	90
	676/4	0	05	47
	667/2	0	27	64
	665	0	13	50
	664	0	12	00
	660/2	0	07	20
	663/1	0	00	50
	662	0	06	45
	661/2	0	06	90
	661/1	0	05	55
	658	0	26	70
	612	0	24	30
	616	0	14	29
	618	0	21	60
	ब्लॉक नं०			
बोरीमसा	979	0	53	25
	793	0	00	25
	कार्ट ट्रेक	0	01	80
	709	0	10	50
	713	0	14	25
	715	0	14	40
	716	0	19	05
	718	0	12	75
	689	0	10	72
	640	0	39	90
	कार्ट ट्रेक	0	00	80
	639	0	12	00
	642	0	00	30
	638	0	14	25
	620	0	15	00

[सं० 12016/2/77-प्रोडक्शन]

टी० पी० सुब्रह्मण्यम, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 1977

S.O. 3919.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 3136 dated 26-9-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Laying Pipeline from GGS VIII to Sokoil TEF Connection
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Villages	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Centiare
Kalol	676/3	0	06	90
	676/4	0	05	47
	667/2	0	27	64
	665	0	13	50
	664	0	12	00
	660/2	0	07	20
	663/1	0	00	50
	662	0	06	45
	661/2	0	06	90
	661/1	0	05	55
	658	0	26	70
	612	0	24	30
	616	0	14	29
	618	0	21	60
	Block No.			
Borisana	979	0	53	25
	793	0	00	25
	Cart track	0	01	80
	709	0	10	50
	713	0	14	25
	715	0	14	40
	716	0	19	05
	718	0	12	75
	689	0	10	72
	640	0	39	90
	Cart track	0	00	80
	639	0	12	00
	642	0	00	30
	638	0	14	25
	620	0	15	00

[No. 12016/2/77-Prod.]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1977

का० भा० 3920—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा II की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से ही परामर्श करने के बाद एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से संबन्धित उक्त अनुसूची में “उक्त अर्हता केवल तभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी जब उसे एक अप्रैल, 1976 को या उसके बाद दिया गया हो और जिसका आधार नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली की तरफ से नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली द्वारा ली गई परीक्षाओं (चाहे वह उक्त तारीख से पहले या बाद में ली गई हो) के परिणाम हो और इसे आन्तरेयी डिग्री के रूप में न दिया गया हो” इस प्रविष्टि के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्—

“मेम्बरशिप ऑफ दी नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम०एन०ए०एम०एम० (शरीर क्रिया विज्ञान)
मेम्बरशिप ऑफ दि नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (सामान्य चिकित्सा)	एम०एन०ए०एम०एम० (सामान्य शल्य चिकित्सा)
मेम्बरशिप ऑफ दि नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)	एम०एन०ए०एम०एम० (सामान्य शल्य चिकित्सा)
मेम्बरशिप ऑफ दि नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (नेत्र विज्ञान)	एम०एन०ए०एम०एम० (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)
मेम्बरशिप ऑफ दि नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (सर्वेदना-हरण विज्ञान)	एम०एन०ए०एम०एम० (नेत्र विज्ञान)
मेम्बरशिप ऑफ दि नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (सर्वेदना-हरण विज्ञान)	एम०एन०ए०एम०एम० (सर्वेदना-हरण विज्ञान)
मेम्बरशिप ऑफ दि नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (सामाजिक एवं निरोधक चिकित्सा)	एम०एन०ए०एम०एम० (सामाजिक एवं निरोधक चिकित्सा)
मेम्बरशिप ऑफ दि नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (मनोरोग विज्ञान)	एम०एन०ए०एम०एम० (मनोरोग विज्ञान)

ये अर्हताएँ केवल तभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी जब उसे तीन अप्रैल, 1977 को या उसके बाद दिया गया हो और जिसका आधार नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली की तरफ से नेशनल प्रकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस द्वारा ली गई परीक्षाओं (चाहे वह उक्त तारीख से पहले या बाद में ली गई हो) के परिणाम हो और इसे आन्तरेयी डिग्री के रूप में न दिया गया हो।”

[सं० बी०-11015/34/76-एम० पी० टी०/एम० ई० (पी०)]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 24th November, 1977

S.O. 3920.—In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule relating to the National Board of Examinations, New Delhi, under the entry, "This qualification shall be a recognised Medical qualification as aforesaid only when granted on or after the 1st April, 1976 on the basis of the results of examinations conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examinations, New Delhi not when conferred as an honorary degree," the following entries shall be added, namely :—

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Physiology)	M.N.A.M.S. (Physiology)
Membership of the National Academy of Medical Sciences (General Medicine)	M.N.A.M.S. (General Medicine)
Membership of the National Academy of Medical Sciences (General Surgery)	M.N.A.M.S. (General Surgery)
Membership of the National Academy of Medical Sciences (Obs. & Gynaecology)	M.N.A.M.S. (Obs. & Gynaecology)
Membership of the National Academy of Medical Sciences (Ophthalmology)	M.N.A.M.S. (Ophth.)
Membership of the National Academy of Medical Sciences (Anaesthesiology)	M.N.A.M.S. (Anaes.)
Membership of the National Academy of Medical Sciences (Social & Preventive Medicine)	M.N.A.M.S. (Soc. & Pre. Med.)
Membership of the National Academy of Medical Sciences (Psychiatry)	M.N.A.M.S. (Psychiatry)

These qualifications shall be recognised medical qualifications as aforesaid only when granted on or after the 3rd April, 1977 on the basis of the results of examinations conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examinations, New Delhi and not when conferred as an honorary degree".

[No. V. 11015/34/76-MPT/ME(P)]

का० आ० 3921—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा II की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के बाद एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम सूची में निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् :—

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से संबंधित उक्त अनुसूची में "आयुर्विज्ञान एकेडेमी के सदस्य.....एम०ए०एम०एस०"

प्रतिष्ठ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिष्ठया अस्तित्वापन की जाएगी, अर्थात् :—

मेम्बर अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज. .एम०ए०एम०एस०	(शरीर क्रिया विज्ञान)	विज्ञान)
मेम्बर अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज. .एम० ए० एम० एस०	(सामान्य चिकित्सा)	चिकित्सा)
मेम्बर अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज. .एम० ए० एम० एस०	(सामान्य शल्य चिकित्सा)	शल्य चिकित्सा)
मेम्बर अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज. .एम०ए०एम०एस०	(प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)	रोग विज्ञान)
मेम्बर अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज. .एम० ए० एम० एस०	(नेत्र विज्ञान)	(नेत्र विज्ञान)
मेम्बर अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज. .एम० ए० एम० एस०	(संवेदनाहरण विज्ञान)	विज्ञान)
मेम्बर अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज. .एम० ए० एम० एस०	(सामाजिक एवं निरोधक चिकित्सा)	एवं निरोधक चिकित्सा)
मेम्बर अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज. .एम० ए० एम० एस०	(मनोरोग विज्ञान)	विज्ञान)

[सं० बी० 11015/34/76-एम पी टी/एम ई (पी)]

आर० बी० श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 3921.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule, relating to the National Board of Examinations, New Delhi, for the entry "Member Academy of Medical Sciences.....M.A.M.S.", the following entries shall be substituted, namely :—

Member Academy of Medical Sciences (Physiology)	M.A.M.S. (Physiology)
Member Academy of Medical Sciences (General Medicine)	M.A.M.S. (General Medicine)
Member Academy of Medical Sciences (General Surgery)	M.A.M.S. (General Surgery)
Member Academy of Medical Sciences (Obstetrics and Gynaecology)	M.A.M.S. (Obst. & Gynaecology)
Member Academy of Medical Sciences (Ophthalmology)	M.A.M.S. (Ophth.)
Member Academy of Medical Sciences (Anaesthesiology)	M.A.M.S. (Anaes.)
Member Academy of Medical Sciences (Social and Preventive Medicine)	M.A.M.S. (Soc. & Prev. Medicine)
Member Academy of Medical Sciences (Psychiatry)	M.A.M.S. (Psychiatry)

[No. V. 11015/34/76-MPT/ME(P)]

R.V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1977

का०आ० 3922—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बनायी गयी स्थायी विन मिति की विनियमावली के विनियम 2(iv) के अनुसरण में

तथा कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम 1940 की धारा 7 में निहित व्यवस्था के अनुसरण में, परिषद् के शासी निकाय द्वारा निकाय के निम्नलिखित सदस्यों को सर्वश्री डी० डी० देसाई व शंकर दयाल सिंह की धनमाप्त कालावधि के लिए प्रार्थना 8 दिसम्बर, 1977 तक प्रत्येक उनके बाद जब तक उनके उत्तराधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन न हो तब तक के लिए परिषद् की स्थायी वित्त समिति का सदस्य चुन लिया गया है —

1. श्री यशवंत राव बोरोले,
लोक सभा सदस्य,
236, जिल्हा पेठ, सेशन कोर्ट के पास
जलगाव तालुका और जिला जलगाव (महाराष्ट्र)
2. श्री ज्योतिर्मय बसु,
लोक सभा सदस्य,
19, बालीगंज स्टेशन रोड,
कलकत्ता-19 ।

[सं० 35(1)/76-सी० डी० एन०-1]

एस० सी० दुता, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (Department of Agricultural Research and Education)

New Delhi, the 16th November, 1977

S.O. 3922.—In pursuance of Regulation 2(iv) of the Standing Finance Committee Regulations framed by the Indian Council of Agricultural Research and in pursuance of provision contained in Section 7 of the A.P. Cess Act, 1940, the following members of the Governing Body of the Council have been elected by that Body to be members of Standing Finance Committee of the Council for the unexpired portion of the term of S/Shri D. D. Desai & Shankar Dayal Singh i.e. upto 8th December, 1977 or till such time thereafter as their successors are duly elected :—

1. Shri Yashwant Borole,
Member, Lok Sabha,
236, Jilha Peth near Sessions Court,
Jalgaon Taluk and Distt, Jalgaon (Maharashtra).
2. Shri Jyotirmoy Bosu,
Member Lok Sabha,
19 Ballygunge Station Road,
Calcutta-19.

[No. 35(1)/76-CDN(I)]

S. C. DUTTA, Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1977

का०आ० 3923.—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री चन्द्रमणि जसुर्वेदी को 23-11-1977 से तथा भ्रमले आदेशों तक एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडलों में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० ए बी-18013/4/75-ए० सी०]

सी० एल० धीगरा, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 28th November, 1977

S.O. 3923.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953) the Central Government hereby appoints Shri C. M. Chaturvedi, Joint Secretary, Ministry of Tourism and Civil Aviation as a Director on the Board of Air-India and Indian Airlines with effect from 23-11-1977 and until further orders.

[No. Av. 18013/4/75-AC]

C. L. DHINGRA, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1977

का०आ० 3924.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी० नागी रेड्डी को तत्काल से भ्रमले आदेश तक, फिल्म सेसर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है ।

[फा० सं० 11/1/77-एफ०सी]

ए० बी० नारायणन, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 1st December, 1977

S.O. 3924.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Cinematograph Act, 1952, the Central Government hereby appoints Shri B. Nagi Reddi as member of the Board of Film Censors with immediate effect until further orders.

[F. No. 11/1/77-FC]

A. V. NARAYANAN, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

का०आ० 3925.—हल्दवानी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बरती किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबको जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (III) (बी बी) में प्रपेक्षित है हल्दवानी में वायु समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनमें कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई प्राप्ति हो या उनके कोई मुद्दा हो तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजने का कष्ट करें ।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बरेली से प्रकाशित होने वाले 'भ्रमर उजाला' समाचार पत्र में तारीख 28-7-77 को प्रकाशित कराई गई थी । उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण में कोई प्राप्ति या और मुद्दा प्राप्त नहीं हुए ।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434 (II) (बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है कि तारीख 1-12-1977 हल्दवानी का स्थानीय संघोद्धित क्षेत्र इस प्रकार होगा :

हल्दवानी एक्सचेंज व्यवस्था

हल्दवानी का एक्सचेंज क्षेत्र वही होगा जो कि हल्दवानी और काठगोबाम नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है :

परन्तु वे टेलीफोन उपभोक्ता जो कि हल्दवानी और काठगोबाम नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते, परन्तु जिन्हें हल्दवानी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्राप्त होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से तब तक 5 कि०मी० की दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से भुगतान करेंगे ।

[सं० 3/6/77-पी० एच० बी०]

पी० एन० कोल, निदेशक फोन (ई)

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 1st November, 1977

S.O. 3925.—Whereas a public notice for revising the local area of Haldwani Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Haldwani, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers,

And whereas the said notice was made available to the public on 28-7-77 in Hindi Daily "Amar-Ujala" published from Bareilly,

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) of the said Rules, the Director General, Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-12-1977 the revised local area of Haldwani shall be as under ;

Haldwani Telephone Exchange System

The local area of Haldwani shall cover an area falling under the jurisdiction of Haldwani cum Kathgodam Municipality :

Provided that the telephone subscribers located outside Haldwani cum Kathgodam municipal limit but who are served from Haldwani Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-6/77-PHB]

P. N. KAUL, Director of Phones(E)

पूति और पुनर्वासि मंत्रालय

(पुनर्वासि विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1977

का०आ० 3926.—निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पूति और पुनर्वासि मंत्रालय (पुनर्वासि विभाग) की अधिसूचना संख्या 15(2)/74-विशेष सेल/एस०एस० 4 दिनांक 17 जुलाई, 1974 का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, पुनर्वासि विभाग में कार्य कर रहे बंदोबस्त आयुक्त श्री प्रेम नारायण को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत या उसके द्वारा अभिरक्षक को सीधे गये कार्यों को निष्पादित करने के लिये संघ गामित क्षेत्र दिल्ली के लिए निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1(26)/विशेष सेल/77 एस०एस० II]

वीनानाथ अमोजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 23rd November, 1977

S.O. 3926.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) No. 15/2/74-Spl. Cell/SS. IV dated 17th July 1974, the Central Government hereby appoints Shri Prem Narain, Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation as the Custodian of Evacuee Property for the Union Terri-

tory of Delhi for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by or under the said Act.

[No. 1(26)/Spl. Cell/77-SS. II]

D. N. ASIJA, Jt. Director

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1977

का०आ० 3927.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वासि) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त इसके द्वारा पंजाब राज्य के पुनर्वासि विभाग के सहायक बंदोबस्त आयुक्त को, पंजाब राज्य में अजिन निष्क्रान्त संपत्तियों, कृषि भूमियों, कुआनों, और खाली स्थलों, जो मुआवजा पूल में आती है, के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 23, 24 और 28 के अन्तर्गत आवश्यक आदेश पारित करने के लिए मुख्य बंदोबस्त आयुक्त की शक्तियां सौंपते हैं।

[सं० 1 (19)/विशेष सेल/76-एस०एस०-II]

ज० चक्रवर्ती, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त

New Delhi, the 24th November, 1977

S.O. 3927.—In exercise of the powers conferred on the Chief Settlement Commissioner by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), he hereby delegates to the Assistant Settlement Commissioner in the Rehabilitation Department of the Government of Punjab the powers of Chief Settlement Commissioner, under sections 23, 24 and 28 of the said Act for the purpose of passing necessary orders under these sections in respect of acquired evacuee properties, agricultural lands, shops and vacant sites, forming part of 'Compensation Pool' in the State of Punjab.

[No. 1(19)/Spl. Cell/76. SS. II]

J. CHAKRABARTY, Chief Settlement Commissioner

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1977

का०आ० 3928.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्पसा रबर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं० 60, पनवेल कोऑपरेटिव इन्डस्ट्रियल एस्टेट, पनवेल, जिला कुलावा, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या हम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(91)/77-पी०एफ० II(i)]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 29th November, 1977

S.O. 3928.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Spasa Rubber Products (Private) Limited, Plot No. 60, Panvel Co-operative Industrial Estate, Panvel District Kolaba, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1976.

[No. S. 35018(91)/77-PF.II(i)]

का०प्रा० 3929—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सब्जि विषय में आदश्यक जांच करने के पश्चात् 30 जून, 1976 से मैसर्स स्पामा रबर प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, प्लॉट नं० 60, पनवेल, कोयामपेरेंट्स इंडस्ट्रियल एस्टेट पनवेल, जिला कुलाबा नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजना के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[स० एम०-35018(91)/77-पी०एफ०-II(ii)]

S.O. 3929.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of June, 1976 the establishment known as Messrs Spasa Rubber Products (Private) Limited, Plot No. 60, Panvel Co-operative Industrial Estate, Panvel District Kolaba, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(91)/77-PF. II(ii)]

का०प्रा० 3930.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोहित इन्डस्ट्रीज, 75-ए०बी०, गवर्नमेंट इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कम्डीवली (वेस्ट), मुम्बई-67 जिसमें 310-311, "नीलम" सी० फेस रोड, बरली, मुम्बई-18 स्थित उसका कार्यालय भी सम्मिलित है, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[स० एम०-35018(94)/77-पी०एफ०-II]

S.O. 3930.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rohit Industries, 75-AB, Government Industrial Estate, Kandivli (West), Bombay-67 including its Office at 310, 311, "Neelam" Sea Face Road, Worli, Bombay-18, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April 1975.

[No. S. 35018(94)/77-PF. II]

का०प्रा० 3931.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री बटापुरेण हाम इन्डस्ट्रीज, बन्तवाल, दक्षिण कनारा, जिसमें अम्नादी बन्तवाल और बन्तीपदप, बन्तवाल स्थित उनकी शाखाएँ भी सम्मिलित हैं, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 जून, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[स० एम०-35019(299)/77-पी०एफ०-II]

S.O. 3931.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shri Vatapur-sh Home Industries, Bantwal, South Kanara including its branches at Amtady Bantwal and Bastipadu Bantwal, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1975.

[No. S. 35019(299)/77-PF. II]

का०प्रा० 3932.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अम्बाल एस्टेट्स कटोर पोस्ट आफिस, नीलगिरिज, मानक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[स० एम०-35019(412)/77-पी०एफ०-II]

S.O. 3932.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ambal Estates, Kataray Post Office, Nilgiris, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1976.

[No. S. 35019(412)/77-PF. II]

का०प्रा० 3933.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम० के० मरवगी एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, त्रिपुरापल्ली, श्रीकाकुलम जिला जिसमें गोदावरी स्ट्रीट विद्यापत्तनम्-1 स्थित उनकी शाखा भी सम्मिलित है, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[स० एम०-35019(415)/77-पी०एफ०-II]

S.O. 3933.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. K. Sarawagi and Company (Private) Limited, Chipurupalli, Srikakulam District, including its branch at Godavari Street, Visakhapatnam-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1976.

[No. S. 35019(415)/77-PF-II]

कां० 3934—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना है कि मैसर्स विशालग्रान्ध इन्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, अजमगढ़ नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एम०-35019(417)/-77-पी०एफ०-II]

S.O. 3934.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vishalandhra Industries, Industrial Area, Azamabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1975.

[No. S. 35019(417)/77-PF-II]

कां० 3935—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना है कि मैसर्स मार्लेन्ड एस्टेट, कुट्टा डाकघर, दक्षिण कुर्ग, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एम०-35019(419)/77-पी०एफ०-II]

S.O. 3935.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Marland Estate, Kutta Post Office, South Coorg, have agreed that the provisions of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1977.

[No. S. 35019(419)/77-PF-II]

कां० 3936—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना है कि मैसर्स बिन्दु वेल, मुकुन्द निवास, उदुपी, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एम०-35019(421)/77-पी०एफ०-II(i)]

S.O. 3936.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bind Well, Mukund Nivas Udipi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July 1977.

[No. S. 35019(421)/77-PF-II(ii)]

नई दिल्ली 3 दिसम्बर, 1977

कां० 3937—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एच० पी० मर्चेंट शक्तिविला, आउट ग्लोर, साबुनम रोड, गामदेवी, मुम्बई-400007 के स्थान पर श्री के० बी० श्रीनिवासन, हाइड्रॉलिक (प्राइवेट) लिमिटेड, 29 माउन्ट रोड, मद्रास को केन्द्रीय न्यायी बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 (ii), तारीख 10 जनवरी, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सं० कां० 236, तारीख 16 दिसम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम में, क्रम संख्या 24 के सामने स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

“(24) “श्री के० बी० श्रीनिवासन, हाइड्रॉलिक (प्राइवेट) लिमिटेड, 29, माउन्ट रोड, मद्रास ।”

[सं० बी०-20012(1)/75-पी०एफ०-II]

New Delhi, the 3rd December, 1977

S.O. 3937.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri K. V. Srinivasan, Hydraulics Private Limited, 29, Mount Road, Madras as member of the Central Board of Trustees, Vice Shri H. P. Merchant, Shakti Villa, Ground Floor, Laburnam Road, Gamdevi, Bombay-400007 and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 236, dated the 16th

December, 1975 published in Part II, section 3 (ii) of the Gazette of India, dated the 10th January, 1976, namely :—

In the said notification against serial number 24, for the entry in column 2 the following entry shall be substituted, namely :—

(24) "Shri K. V. Srinivasan, Hydraulics (Private) Limited, 29, Mount Road, Madras"

[No. V-20012/1/75-PF.II]

कां० प्रा० 3938—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 3 के उप-पैरा (i) के खण्ड (घ) के अनुसूचन में, श्री जतिन चक्रवर्ती, अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल राज्य समिति, संयुक्त व्यापार संघ कांग्रेस के स्थान पर श्री मतीश राय, सचिव, पश्चिमी बंगाल राज्य समिति, संयुक्त व्यापार संघ कांग्रेस, 249 बी० बी० गांगुली स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कलकत्ता को पश्चिमी बंगाल राज्य के लिये बनाई गई प्रादेशिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3(ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां० प्रा० 238 तारीख 18 विमम्बर, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 9 के सामने, स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री मतीश राय, सचिव
पश्चिमी बंगाल राज्य समिति,
संयुक्त व्यापार संघ कांग्रेस,
249-बी० बी० गांगुली स्ट्रीट, दूसरी मंजिल,
कलकत्ता।"

[सं० बी०-20012/12/72-पी०एफ०-II]

एम्० एम्० महसनामत, उप-सचिव

S.O. 3938.—In pursuance of clause (d) of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby appoints Shri Matish Roy, Secretary, West Bengal State Committee, United Trade Union Congress, 249, B. B. Ganguly Street, 1st Floor, Calcutta, as a member of the Regional Committee set up for the State of West Bengal vice Shri Jatin Chakravorty, President West Bengal State Committee, United Trade Union Congress and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 238, dated the 18th December, 1975, published in part II, Section 3(ii) of the Gazette of India, dated the 10th January, 1976, namely :—

In the said notification, against serial number 9, for the entry in column number 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Matish Roy, Secretary, West Bengal State Committee, United Trade Union Congress, 249, B. B. Ganguly Street, 1st Floor, Calcutta".

[No. V-20012/12/72-PF. II]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1977

कां० प्रा० 3939—केन्द्रीय सरकार के यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसूचन में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां० प्रा० 1852 तारीख 16 मई, 1977 द्वारा बैंक नोट प्रैम, देवान में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये

26 मई, 1977 से छः मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार को राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 26 नवम्बर, 1977 से छः मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी लेखा सेवा घोषित करती है।

[संख्या एम्०-11017(14)/76-डी०-I(ए०)]

New Delhi, the 26th November, 1977

S.O. 3939.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1852 dated the 16th May, 1977 the Service in the Bank Note Press, Dewas, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 26th May, 1977;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 26th November, 1977.

[No. S. 11017/14/76/DI(A)]

नई दिल्ली, 1 विमम्बर, 1977

कां० प्रा० 3940—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक नियोजन (स्थायी प्रादेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 13क के अनुसूचन में, (i) नई दिल्ली में, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० कां० प्रा० 4286, तारीख 30 सितम्बर, 1976 के अन्तर्गत और (ii) हैदराबाद में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० कां० प्रा० 456, तारीख 5 फरवरी, 1976 के अन्तर्गत, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालयों को ऐसे श्रम न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें कोई भी नियोजक या कर्मकार ऐसा कोई भी प्रश्न निवेष्ट कर सकता है जो पूर्वोक्त औद्योगिक नियोजन (स्थायी प्रादेश) अधिनियम के अधीन प्रमाणित स्थायी प्रादेशों को लागू होने या उनके निर्वहन के बारे में उत्पन्न हो।

[सं० एम्०-12011/1/77-डी० I(ए०)]

एल० के० नारायण, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st December, 1977

S.O. 3940. In pursuance of section 13A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), the Central Government hereby specifies the Labour Courts, constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), at (i) New Delhi, constituted under Ministry of Labour Notification No. S.O. 4286, dated the 30th September, 1976 and (ii) Hyderabad, constituted under the then Ministry of Labour and Employment, Notification No. S.O. 456, dated the 5th February, 1976, as Labour Courts to which any employer or workman may refer any question which may arise on the application or interpretation of a Standing Orders, certified under the Industrial Employment (Standing Orders) Act aforesaid.

[No. S. 12011/1/77/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

New Delhi, the 5th December, 1977

S.O. 3941.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Grindlays Bank Ltd., Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on 16-11-77.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
NEW DELHI

I.D. No. 174/77

In re :

The Secretary, U.P. Bank Employees' Union, C/o
Bank of Baroda, Latouche Road, Kanpur.

Versus

The Manager, Grindlays Bank Ltd., 16, Mahatma
Gandhi Road, Kanpur.

PRESENT :

Shri R. C. Pathak—for the Union.

Shri K. K. Khullar—for the Bank.

AWARD

The Central Government vide its order No. L. 12011/38/76-D.II.A, dated the 28th September, 1976 made the following reference to Industrial Tribunal, Delhi :

'Whether the action of the management of the Grindlays Bank Limited, Kanpur in discontinuing supply of towels/angochas to Subordinate staff of the Kanpur Branch of Bank from 1976 is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?'

2. After the parties had appeared before the Industrial Tribunal, Delhi this case was ordered to be transferred to this Tribunal for disposal and it is in these circumstances that it has come up before me.

3. The petitioner—Union has filed a statement of claim and in reply thereto it was submitted by the Management that 'without prejudice to their rights the Management will continue henceforth to supply angochas/towels to each of the members of the subordinate staff mentioned in the Annexure-I to the statement of claim dated 31-1-1977 filed by the union'.

4. In view of this petition having been filed in reply to the statement of claim of the workmen Shri K. K. Khullar, the authorised attorney for the Bank and Shri R. C. Pathak, authorised attorney for the union came forward with a statement in the following term :

'In this reference an application was made by the Management on 9th September, 1977 which is Ex. C/1. In pursuance thereof the union is agreeable to the proposed in Ex. C/1 without prejudice to other rights. This matter stands settled and an award be made in this case accordingly'.

5. It is in these circumstances that it is hereby awarded that 'without prejudice to the rights of the Management and other rights of the workmen the management would continue henceforth to supply angochas/towels to each of the members of the subordinate staff mentioned in Annexure I to the statement of claim dated 31-1-1977 filed by the union before this tribunal. Annexure-I to the statement of claim would form part of this award. Parties would bear their own costs in this reference. Requisite copies of the award may be sent to the appropriate Government for necessary action.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[F. No. 12011/38/76-D. II. A.]

Dated : 15th September, 1977.

S.O. 3942.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Nagpur and their workmen which was received by the Central Government on 24-11-77.

118GI/77-4

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. CGIT-9 of 1971

Employers in relation to the Central Bank of India,
AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Management—Shri K. C. Dhondy, Chief Officer.

For the workmen—Shri S. P. Choudhari, President,
Vidharbha Bank Employees Federation.

INDUSTRY : Banking.

STATE : Maharashtra

Bombay, the 17th October, 1977

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, by its Order No. L. 12012/57/71/LR-III, dated the 29th October, 1971, referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the I.D. Act.

SCHEDULE

"Whether the non-absorption of Shri A. N. Ratnaparkhi, Clerk-cum-typist in the permanent staff of the Central Bank of India, Amravati Branch was legal and justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

After the parties had filed their respective written statements, the matter was fixed for hearing on a number of occasions but these were adjourned for one or another reason. However, at the hearing on 17-10-1977 the parties filed a joint application stating that they had arrived at an amicable settlement and prayed that this Hon'ble Tribunal be pleased to pass an order in terms of the Settlement (Annexure-A).

I have gone through the terms of settlement and find them fair and reasonable and pass my Award in terms of the Settlement. Under the Circumstances no cost is being paid.

J. NARAIN, Presiding Officer,

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL, BOMBAY

Reference No. 9/71/379/76-CGIT 9 of 1971

In the matter of Industrial Dispute between the Management of Central Bank of India, Amravati,

AND

Their Workmen as represented by the Vidharbha Bank Employees Federation.

Shri S. P. Choudhari, the President of the Vidharbha Bank Employees Federation on behalf of the Federation and Shri A. N. Ratnaparkhi the workman concern and the opposite party, viz., the Central Bank of India, beg to submit as under :

"That the parties to the above dispute have arrived at an amicable settlement as per the mutual negotiations held between the parties. It is, therefore, prayed that the Honourable Tribunal may be pleased to pass an order that the dispute has been resolved in term, of the Settlement annexed hereto."

For Central Bank of India

Sd/-

K. C. DHONDY, Chief Officer.

Witness :

Sd/-

S. P. CHOUDHARI, President,

F. M. BHAMGARA

Vidharbha Bank Employees Federation.

Witness :

Sd/-

(ASRAN)

Bombay,
17th October, 1977.

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. 9/71/379/76-CGIT 9 of 1971

In the matter of Industrial Dispute between the Management of Central Bank of India, Amravati.

AND

Their Workmen as represented by the Vidharbha Bank Employees Federation.

Shri S. P. Choudhari, the President of the Vidharbha Bank Employees Federation on behalf of the Federation and on behalf of Shri A. N. Ratnaparkhi the concerned workman and the opposite party viz., the Central Bank of India, have arrived at the following Settlement:

"That the Bank will pay a sum of Rs. 2000 (Rupees Two thousand only) in full and final settlement of the claim of Shri Ratnaparkhi and that in consideration thereof, Shri Ratnaparkhi agrees not to press any claims either for damages or for reinstatement in service and the Union agrees not to pursue the claim made in the application."

For Central Bank of India

Sd/-
K. C. DHONDY, Chief Officer

Witness

Sd/-
F. M. BHAMGARA, Manager.

J. NARAIN, Presiding Officer
[F. No. L-12012/57/71-LR. III/D. II.A.]

Sd/-

S. P. CHOUDHARI, President,
Vidharbha Bank Employees Federation.

Witness

Sd/-
ASRAN

Bombay.

17th October, 1977.

S.O. 3943.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Grindlays Bank Ltd., Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-11-77.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. CGIT-11 of 1976

Employers in relation to Grindlays Bank Ltd., Bombay.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the workmen—Shri P. N. Subramanyam, General Secretary National & Grindlays Bank Employees Union, Bombay.

For the Employers—Shri R. K. Ghotkulkar, Manager, Industrial Relations, Grindlays Bank, Bombay.

INDUSTRY : Banking.

STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 18th October, 1977

AWARD

The Government of India, in the Ministry of Labour, by its Order No. L-12012/123/76-D.II.A., dated the 6th October, 1976 referred the following dispute for adjudication by this Tribunal under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Grindlays Bank Ltd., Bombay in terminating the services of Shri D. M. Patil, Subordinate Staff, Mint Road, branch, Bombay is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

After the parties filed their respective written statements, etc. the matter was fixed for hearing on a number of occasions. However, at the last hearing that is on

18-10-1977, the Management filed an application stating therein that without admitting any of the submissions made by or on behalf of the Workman Mr. D. M. Patil in respect of this dispute and without prejudice to the Bank's submissions and contentions in the matter, purely on compassionate and humanitarian grounds and as a special case the Bank offers to re-instate Mr. D. M. Patil in service with continuity of service but without entitlement to any pay and allowances or any other benefits for the period from 16-9-1975 till the date he reports for duty, provided he reports for duty on or before 18th November, 1977. In case Mr. D. M. Patil fails to report for duty on or before 18th November, 1977, this reference will be answered in favour of the Bank i.e. the action of the Bank in terminating the service of Shri D. M. Patil will be held as justified and he will not be entitled to any relief. The Management prayed that this Hon'ble Tribunal be pleased to accept its above submission and make an Award in terms thereof with no order as to costs.

Without prejudice to its submissions and without admitting the submissions of the Bank in the matter of dispute, the Union has no objection to the proposal made by the management.

Under the circumstances, I make my award accordingly.

J. NARAIN, Presiding Officer
[No. L-12012/123/76-D.II.A.]

New Delhi, the 8th December, 1977

S.O. 3944.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Andhra Pradesh in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Hyderabad and their workman which was received by the Central Government on the 21st November, 1977.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 9 of 1977

BETWEEN

Workman of State Bank of India, Avanigadda Branch.

AND

The Management of State Bank of India, Hyderabad.

APPEARANCES :

Sri P. Venkateswara Rao, Joint Secretary of State Bank of India Staff Union, Hyderabad—for Workman.

Sri A. V. Chalapathy Rao, Law Officer, State Bank of India, Hyderabad—for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, through its Order F. No. L-12012/12/77-D.II.A. dated 6-6-1977 referred under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 the following dispute existing between the Employers in relation to the Management of the State Bank of India, Avanigadda, Krishna District and their Workman to this Tribunal for adjudication.—

"Whether the action of the Management of the State Bank of India, Avanigadda Branch, Krishna District, in terminating the services of Shri G. Bhaskar Rao, Cashier, Avanigadda Branch of the Bank with effect from 24-5-1971 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 9 of 1977 and notices were ordered to be issued to the parties.

3. The workman represented by the Joint Secretary, State Bank of India Staff Union, Andhra Pradesh, Hyderabad filed a claims statement contending as follows:—The workman concerned in this dispute was originally appointed as Cashier on a temporary basis on 1-4-1970 and was continued in service till 24-5-1971. His services were terminated with effect from 24-5-1971 by the Management on the ground that his appointment was temporary in nature. The vacancy in which the workman was employed was at all times a permanent vacancy and he was not employed to discharge work of a purely temporary character. Hence the termination amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act, 1947.

The workman had worked as Cashier continuously for more than fourteen calendar months. He could not have been retrenched until he was paid retrenchment compensation under section 25F of the Act. Since the Management did not comply with this mandatory requirement the retrenchment order dated 24-5-1971 is invalid and inoperative. It is essential and in the interests of justice that the said orders should be set aside and the workman should be reinstated with full back wages from the date of the termination of his employment. The workman could not get any employment, in spite of his best efforts, though he is a graduate. The State Bank of India Staff Union Andhra Pradesh espoused his cause and raised an industrial dispute. Since the conciliation failed this dispute has been referred to this Tribunal. It is therefore requested that the Management may be directed to reinstate the workman in service with full back wages from the date of his termination together with all attendant benefits.

4 The Management of the Bank filed a counter contending as follows—The reference is bad since the Union which espoused the cause of the workman has no backing of a substantial or appreciable number of employees. The workman was appointed as Cashier on a temporary basis in the Avanigadda Branch from 1-4-1970 on a clear understanding that the temporary appointment would not confer on him any right to claim absorption in the Bank's permanent establishment. He was discharged from service on 24-5-1971 as there was no longer any necessity to continue a temporary employee. Since the workman did not protest at the time of the receipt of the order of discharge and withdrew the amount of Security Deposit, he is estopped from questioning the order of discharge. He was allowed to appear for the Bank's competitive examination in view of his temporary service to qualify himself for a regular post as it is a condition precedent for securing a permanent post in the Bank. But he could not pass the test. He is therefore not entitled to permanent appointment. Temporary service does not entitle a workman to a permanent post if he does not pass the test. The workman's claim is stale and belated. He did not choose to put forward a demand for six years. The Bank has an arrangement with the Staff Federation which is the only representative Union of the workmen and staff, on the subject of absorption of temporary employees who have put in more than 240 days of service in a year and were in service on 1-1-1975. The Petitioner's case is not one of retrenchment but it is only one of discharge for want of vacancy. Hence the claim is liable to be rejected.

5 On behalf of the workman a rejoinder was filed contending as follows—The Union had about 2,000 members at the time when the dispute was raised and it has a substantial number to espouse the cause. Withdrawal of security deposit, which was done by the workman only for sustaining himself as he had no other income, has no relevancy. Security Deposit is required only when an employee performs Cashier's duties and handles cash. Withdrawal of the deposit does not take away the right of the employee to seek reinstatement. The employee still can deposit the amount when he is reinstated. The object and purpose of conducting the test is to find out the suitability of a candidate for employment. When the employee actually worked to the satisfaction of his superiors and when his suitability was thoroughly tested over a period of fourteen months there is no necessity to hold a test again. Even after a written test and interview the Bank prescribes a period of six months of probation for finding out if a candidate is suitable for continuance in the Bank's service. The workman concerned had worked for more than twice the probationary period. There were no adverse remarks on his work conduct and character. On the other hand he was given an excellent certificate by the Branch Manager when his services were terminated. There is no limitation for raising an industrial dispute. The workman waited for about two years in the hope that the Bank would reinstate him sooner or later. As there were no immediate tests he waited for such a long period. The employee ultimately raised the dispute before the Assistant Labour Commissioner (Central) Vijayawada in 1974 which led to the reference in 1977. The workman is therefore not responsible for the delay. No Union or Management can enter into any arrangement or agreement which will nullify or take away the rights guaranteed to the workman under the provisions of a statute. The Bank appointed other permanent employees in the vacancies of Sri G. Bhasker Rao and other temporary employees working at the material time in the Avanigadda Branch.

6 The Management filed a reply to the workman's rejoinder contending as follows—The Management denies that the Union had 2,000 members at the time when the dispute was raised. It had only about 900 members in 1974 which has dwindled to about 500 at present. Withdrawal of the Security Deposit without protest would amount to giving up of the rights to the post. The workman was permitted to appear for the test thrice to qualify himself for permanent absorption. The mere fact that he worked for about fourteen months would not entitle him to get himself permanently appointed without passing the test. The certificate issued by the Agent of the Avanigadda Branch on 15-6-1971 has no relevance. No employee is confirmed in the Bank's service without successful completion of probation. His performance during the period of temporary service will not be taken into consideration. It is no excuse to say that the workman waited for two years in the hope of getting an appointment after qualifying himself in the tests that might be conducted after 1972. Nothing prevented him from moving the machinery under the Act while waiting to qualify himself in the test.

7. No witness was examined on behalf of the workman concerned. MW 1 who has been working as an Officer in the Personnel Department since April, 1976 is the only witness examined on behalf of the Management. Exs W1 to W13 were marked on behalf of the workman and Exs M1 to M9 on behalf of the Management.

8 The workman concerned in this dispute is G. Bhasker Rao and he is a Graduate. Ex M1 is the photostat copy of the order dated 1-4-1970 by which he was appointed as Cashier in the Avanigadda Branch of the State Bank of India with effect from 1-4-1970 until further orders on a salary of Rs 188.00 per month and Dearness Allowance. This order shows that the appointment would not confer on the workman any right to claim absorption in the Bank's permanent establishment in any category. By means of Ex W1 the order dated 24-5-1971 his services were terminated with effect from even date. No reasons necessitating or justifying the termination of the workman's services were mentioned in Ex W1. Admittedly no compensation under section 25F of the ID Act, 1947 was paid to him when his services were terminated. The Agent of the Avanigadda Branch issued Ex W2 the certificate dated 15-6-1971 mentioning that the workman had been in service for fourteen months from 1-4-1970 to 24-5-1971, that he was getting Rs 320.00 per month towards his salary and allowance and that his conduct and character were excellent. The workman had deposited a sum of Rs 1,000.00 by way of Security. Out of that amount he withdrew Rs 900.00 on 24-5-1971, the date on which he was discharged. Ex M9 is the extract from the security account relating to the workman concerned which bears out this fact. Exs W3 to W10 are relied upon to show that the workman's efforts to secure alternative employment did not bear fruit. The Bank conducted qualifying tests to enable temporary personnel to qualify themselves for absorption on permanent basis. Ex M2 shows that the present workman appeared for the test held on 9-8-1970. The corresponding list of successful candidates relating to that test is Ex M5 and it does not include this workman's name. Ex M3 is the list of candidates who appeared for the test held on 9-5-1971 and this shows that the workman took that test. Ex M6 which is the corresponding list of successful candidates relating to that test does not contain his name. The aforesaid two tests were held when this workman was in service. After his discharge another test was held on 24-9-1972 and this workman's name is found in Ex M4 which is the list of the candidates who appeared for that test. He did not pass even that test as seen from Ex M7 the list of successful candidates. Ex M8 is a series of Circulars issued by the Bank from which it can be gathered that a test consisting of English, Arithmetic and General Knowledge was held in January 1974 for temporary employees who had put in nine months of service by the date of the test so that those who qualified in the test with an aggregate of at least 35 marks could be wait-listed and taken on probation as and when vacancies arose. Requests made by the All India State Bank of India Staff Federation, which is the only recognised Union requesting that those who had put in a temporary service of 12 months might be exempted from the rest was not complied with and this fact is stated by MW 1. Ex M8 series are not of much significance since they relate to a period subsequent to the termination of this workman's services. As this workman failed to qualify himself even in the test held in 1972 the vacancy caused by his discharge was filled up.

by another candidate. When the workman addressed the Labour Commissioner (Central), Vijayawada through the Union, Ex. W12 the letter dated 27-7-1976 was sent by way of reply stating that his case had already been closed and could not be reopened. But the matter appears to have been taken in conciliation subsequently along with the case of certain other employees similarly placed. Ex. W13 is the failure report dated 31-1-77 submitted by the Assistant Labour Commissioner (Central), Vijayawada to the Government reporting failure of conciliation. Thereafter the present reference was made.

9. M.W.1 states that in 1974 there were about 900 members in this Union and that there are about 6,000 workmen in the Circle at present. His evidence is further that even though a person has put in temporary service he must complete six months' period of satisfactory probation before he is entitled to confirmation and that for purposes of confirmation his service during the probation period alone would be taken into consideration. M.W.1 refers to an agreement between the Management and the Staff Federation which is the recognised body to the effect that, if a person who has completed 240 days of service was discharged after 1-1-1975, he should be reinstated on a temporary basis on his application. He admits that the qualifications required for temporary as well as permanent appointment are generally the same, that a person would not be allowed to continue in employment for any length of time on temporary basis if he was found to be unsuitable to hold such employment. He adds that apart from the fact that this workman did not qualify himself in the test there was nothing on record to show that he was unsuitable for employment as Cashier. It is admitted by him that tests are held normally when there are some people working on temporary basis and with a view to filling up of permanent vacancies and further that a person who is temporarily appointed as Cashier may also be transferred to some other department such as Clerical Department in which case he would not be required to make a Security Deposit. He states that in about 1974 the total number of workmen in Hyderabad Circle may be around 4,000.

10. On behalf of the Management a preliminary objection is raised to the effect that since the Union which sponsored the cause of the present workman does not represent a substantial or an appreciable number of the workers, there is no proper espousal justifying the reference and that this is not an industrial dispute but only an individual dispute which could not be adjudicated upon under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 but should be resolved through the machinery provided by the Andhra Pradesh Shops and Establishment Act, 1966. In support of this contention reliance is placed upon the decision in *VAZIR SULTAN TO-BACCO C. v. STATE OF A. P.* [1964 (1) LLJ Page 622]. In that case when a workman was dismissed the dispute regarding his dismissal was taken up by 104 co-workmen out of 2,170 workmen in the establishment and it was espoused by a Union of which workmen in other similar establishments were members. It was held that their support could not convert the individual dispute into an industrial dispute. M.W.1's evidence is that there are about 500 members in the State Bank of India Staff Union, Andhra Pradesh which has espoused the cause of the present workman and that there are about six thousand workmen in the Circle at present. But M.W. 1 admits that he came to know about this fact only a few days before giving evidence from other officers in the personnel department. He has therefore no personal knowledge of the strength of the sponsoring Union. The concerned workman has been agitating his claims since about 1974. M. W. 1 admits that in about 1974 the total number of workmen in Hyderabad Circle may be around 4,000. In the rejoinder filed by the workmen it is alleged that this sponsoring union had about 2,000 members at the time when the dispute was raised. This averment is denied by the Management in their reply to the rejoinder. But it is alleged therein that in 1974 this Union had only about 900 members. Hence the sponsoring Union had a membership of about 900 as against the total number of about 4,000 workmen in 1974 when the dispute was sponsored by it. It cannot be said that nearly 1/4th of the total number of workmen is not a substantial or appreciable section. When such is the case there is no point in contending that there has been no proper espousal of the concerned workman's cause by a substantial or appreciable number of workmen pertaining to the establishment. I therefore hold that the dispute is

properly sponsored and that it is not merely an individual dispute but an industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the I. D. Act and that this Tribunal is competent to adjudicate upon it. The preliminary objection therefore fails.

11. The workmen's contention is that the order Ex. W. 1 which terminated his services with effect from 24-5-1971 is virtually an order of retrenchment within the meaning of Section 2(OO) of the Industrial Disputes Act, 1947. On the other hand it is contended by the Management that it is only a case of discharge and not retrenchment, since the concerned workman was appointed purely on a temporary basis under Ex. M. 1. In paragraph 3 of the Management's counter it is alleged that this workman was discharged from service as there was no necessity to continue a temporary employee. Again in paragraph 6 of the Management's counter it is stated that this is a case of discharge for want of vacancy. Since it is admitted that after the present workman's services were terminated under Ex. W. 1 another incumbent was appointed in his place, it cannot be contended that the present workman was discharged for want of vacancy. On the other hand the vacancy still exists. It is seen from Ex. W. 2 that this workman was in service as Cashier in the Avanigadda Branch of the State Bank of India from 1-4-1970 to 24-5-1971, that is, for a period of about 14 months. As a matter of fact Ex. M. 1 does not specify the period of the concerned workman's employment but it merely states that he was appointed as a temporary cashier with effect from 1-4-1970 until further orders. In *STATE BANK OF INDIA v. SUNDARAMONEY* [1976- (1) LLJ, page 478 S. C. at page 482 column 2] it was held as follows :—

"A break-down of Section 2(OO) unmistakably expands the semantics of retrenchment, "termination...for any reason whatsoever" are the key words. Whatever the reason, every termination spells retrenchment. So the sole question is has the employee's service been terminated? Verbal apparel apart, the substance is decisive. A termination takes place where a term expires either by the active step of the master or the running out of the stipulated term. To protect the weak against the strong this policy of comprehensive definition has been effectuated. Termination embraces not merely the act of termination by the employer but the fact of termination, howsoever produced."

It is clear from the aforesaid passage that even a case of automatic cessation of employment brought about by efflux of time or by disappearance of the need for continued employment would amount to retrenchment within the meaning of Section 2(OO), despite the fact that it was not brought about by any volition on the part of the employer. Hence this is clearly a case of retrenchment within the meaning of Section 2(OO). Section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 lays down the conditions subject to which retrenchment of workers can be ordered. The first and foremost condition is that no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer unless the workman has been given one month's notice in writing or unless he has been paid wages for the notice period. Admittedly this condition relating to notice or pay in lieu of notice has not been complied with in the case of this workman. Another condition is that at the time of retrenchment compensation at a certain rate should be paid to the retrenched workman. Admittedly even this condition was not complied with. Another provision that has to be considered in this context is Section 25G which embodies the salutary principle of 'last come first go' in the matter of retrenchment. Section 25H deals with re-employment of retrenched employees in the inverse order of retrenchment. These rights accrue only to workmen who have been in continuous service for not less than one year under the employer. The expression "continuous service for not less than one year" occurring in Section 25F of the I. D. Act, 1947 is defined in Section 25B. Two conditions are laid down in Section 25B and both the conditions must be satisfied if a workman is to be deemed to be in continuous service for not less than one year. The first condition is that the workman should have worked during a period of one year preceding the date with reference to which the calculation has to be made and the

second condition is that during the said period he must have actually worked for not less than 240 days. In order to claim the benefits of Sections 25F, G and H it must be shown, first, that the workman concerned was employed during the 12 months preceding 25-4-1971 and secondly that during the 12 months preceding that date he had worked for not less than 240 days. Both these conditions are satisfied in the case of the present workman. He is therefore, entitled to the reliefs provided for under Sections 25F, G and H. Since admittedly no compensation was paid to this workman under Section 25F his retrenchment is void and inoperative. In fact the Management entered into an arrangement with the recognised Union to re-employ persons discharged after 1-1-1975 if they had put in 240 days of service. But the benefit of this arrangement did not accrue to the present workman because he was retrenched long before 1-1-1975. However, this arrangement appears to have been entered into in recognition of the right which accrues to a workman, though his tenure of employment might be temporary. There is no reason why the same principle should not be extended to the present workman. It has therefore to be held that the order Ex. W. 1 is an order of retrenchment passed without complying with the mandatory provisions contained in Section 25F of the I. D. Act, 1947 and the said order is therefore invalid in law.

12. It is also argued on behalf of the Management that by withdrawing a substantial portion of the cash deposit on the date of the termination of his service, the present workman indicated acquiescence in the orders passed as per Ex. W. 1. In this connection reliance is placed upon Ex. M.9. But the explanation offered on behalf of the concerned workman is that he was constrained to withdraw the amount of security deposit only to sustain himself and not because he gave up his rights. Moreover it is admitted by M. W. 1 that if a person temporarily appointed as a Cashier is transferred to some other department such as Clerical Department he would not be required to make a Security Deposit. There is no question of estoppel arising from this workman's action in withdrawing the security deposit amount. Hence the Management cannot derive any support from that circumstance.

13. It is also urged for the Management that the concerned workman did not qualify himself for absorption on a permanent basis though he took the tests thrice and that he could not be considered for re-employment. It is in M. W. 1's evidence that the qualifications required for temporary as well as permanent appointment are generally the same, that a person would not be allowed to continue in employment for any length of time even on a temporary basis if he was found to be unsuitable to hold such employment and that apart from the fact that this workman did not qualify himself in the tests, there was nothing on record to show that he was unsuitable for employment as cashier. Hence the fact that this workman did not pass the qualifying test is of no consequence as far as Section 25F of the Industrial Disputes Act 1947 is concerned.

14. Another contention put forward on behalf of the Management is that when the services of this workman were terminated on 24-5-1971, the reference was issued on 6-6-1977 after a delay of more than six years and that the dispute has therefore become stale and is belated. Reliance is placed upon the decision in *VAZIR SULTAN TOBACCO CO. v. STATE OF A. P.* (1964(1) L.J. page 622) wherein it was held that the inordinate delay of 4 1/2 years in making the reference was both unreasonable and unjustified. Exs. W. 3 to W. 10 show that the present workman has all along been making frantic efforts to secure alternative employment but without any success. Ex. W. 11 shows that even prior to 1975 he had moved the concerned authorities for redressal of his grievances. This is not a case of supine indifference on the part of the retrenched employee justifying the rejection of his claim. On the other hand it looks as though there has been a long lapse of time for reasons beyond the workman's control. I am therefore of the opinion that merely because there was delay in referring the dispute for adjudication, the concerned workman's claim should be rejected out of hand as being belated.

15. For all these reasons I hold that the action of the Management of the State Bank of India, Avangadda Branch, Krishna District in terminating the services of the workman G. Bhaskara Rao, Cashier with effect from 24-5-1971 is

illegal and unjustified, and that he should therefore be reinstated in service.

16. The Management did not adopt a vindictive attitude towards this workman and the termination of his services cannot be characterised as an unfair labour practice. The Management afforded three opportunities to the workman to qualify himself for regular appointment but the workman could not take advantage of the opportunities he had. Considering these circumstances I am of the view it is enough if the concerned is reinstated in service with effect from 24-5-1971 with only 1/3rd of the back wages.

An award is hereby passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 29th day of October, 1977.

K. P. NARAYANA RAO, Indus. Tribunal.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined For Workmen :	Witnesses Examined For Management :
Nil.	M. W. 1 Shri P. S. Sarma.

Documents Exhibited For Workmen :

- Ex. W. 1 Termination order of Shri G. Bhaskara Rao, Cashier, State Bank of India, passed by the State Bank of India dated 24-5-1971.
- Ex. W. 2 Conduct and Character Certificate issued by the Respondent to Shri G. Bhaskara Rao on 15-6-1971.
- Ex. W. 3. Transfer of Employment Card from Hyderabad Employment Exchange to Employment Exchange, Vijayawada through their Lr. No. C/Trans/76-77, dated 22-11-1976.
- Ex. W. 4. Employment card of Shri G. Bhaskara Rao, in Vijayawada Employment Exchange.
- Ex. W. 5. Letter of the A. P. Coop. Central Land Mortgage Bank Ltd. Hyd. through its Lr. No. 236/73-74/P. A. I. dated 17-5-1974 addressed to Shri Goriparthi Bhaskara Rao regarding the cancellation of the advertisement in the news papers.
- Ex. W. 6. Lr. No. Est./7794/dated 7-9-1977 from the A. P. State Coop. Bank Ltd. Hyderabad addressed to Shri G. Bhaskara Rao regarding recruitment of Staff Assistants.
- Ex. W. 7. Call Letter for a vacancy in State Bank of India, Vuyyuru, of Employment Exchange, Vijayawada given to Shri G. Bhaskara Rao.
- Ex. W. 8. Card of Certificate of Posting sent by the applicant to the Employment Office, Suryanao Pet, Vijayawada on 7-5-1974.
- Ex. W. 9. Postal Ack. Due forms two in number sent by Shri G. Bhaskara Rao addressed to the Recruiting and Training Officer, A. P. S. R. T. C. Mushirabad, Hyderabad and the Chief Personal Security Officer, A. P. S. R. T. C., Mushirabad, Hyderabad on 16-10-1975.
- Ex. W. 10. Telegram issued by Shri Adishesu to Shri G. Bhaskara Rao informing the dates of interview on 6-6-1974.
- Ex. W. 11. Copy of representation of Shri G. Bhaskara Rao, Ex-Cashier, State Bank of India, Avangadda for reinstatement in the said branch sent by the Asst. Labour Commissioner (C) Vijayawada on 15-4-1975.
- Ex. W. 12. Letter of the Asst. Labour Commissioner (C), Vijayawada dated 27-7-1976 addressed to the Joint Secretary, State Bank of India Staff Union

Andhra Pradesh, Peddibhotlavari Street, Vijayawada regarding termination of Shri Goripathi Bhaskara Rao in violation of I. D. Act.

- Ex. W. 13. Copy of the L.J. No. 7/4/77-ALC-BZA., dated 31-1-1977 from the Asst. Labour Commissioner (C), Vijayawada regarding failure of Conciliation.

Documents Exhibited For Management :

- Ex. M. 1. Photo state copy of the appointment order of Shri G. Bhaskara Rao, Mangalapuram issued by the State Bank of India, Avanigadda, on 1-4-1970.
- Ex. M. 2. Statement showing the list of candidates who were permitted to appear for cashiers test held at Eluru on the 9th August, 1970 on account of Avanigadda Branch.
- Ex. M. 3. Statement showing the particulars of direct candidates in respect of clerks in Masulipatnam centre on 9-5-1971.
- Ex. M. 4. Statement showing the particulars of temporary candidates who were permitted to appear for the N. I. B. M. test held at Kakinada on 24-9-1972.
- Ex. M. 5. Statement showing the list of candidates selected branch-wise in order of merit in Eluru Branch for cashiers recruitment test held on 9-8-1970.
- Ex. M. 6. Statement showing the list of successful candidates in written test held on 9-5-1971 in Masulipatnam centre.
- Ex. M. 7. Statement showing the particulars of temporary candidates who had passed in the written test held at Kakinada on the 24-9-1972.
- Ex. M. 8. Circulars (in series) dated 13-11-1973 issued by the Personal Department of State Bank of India regarding permanency of Clerical & Cash Departments temporary employees.
- Ex. M. 9. Extract of the Security Account of Shri G. Bhaskara Rao, Ex. temp. Cashier for the period 1-4-1970 to 14-12-1973.

K. P. NARAYANA RAO,
Presiding Officer

[F. No. L. 12012/12/77-D. II. A.]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

S.O. 3945.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal cum-Labour Court No. 2 Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. V. M. Salgaocar & Bros. Private Limited Goa and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th November, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL

TRIBUNAL No. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/10 of 1973

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs V. M. Salgaocar & Brother Private Limited.

AND

Their Workmen.

1. Shri Prabhakar Vengurlekar
2. Shri Ganesh Gotambikar
3. Shri Shrikant Valvoicar
4. Shri Arjunhe Venkatappa
5. Shri Sadanand Pileinekar

6. Shri Suryakant Gavande
7. Shri Shivaji Dhargalkar
8. Shri Jayeshwar Aldonkar
9. Shri Suryakant Chodankar
10. Shri Babni Amonkar
11. Shri Shaik Inus
12. Shri Chandrakan Curtorkar
13. Shri Narayan Palyenkar
14. Shri Ambrose Lawrence
15. Shri Nanco B. Gaoncar

through the Goa Mining Labour Welfare Union.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. K. Iale, Industrial Relations Officer.

For the workmen—Shri George Vaz, General Secretary, Goa Mining Labour Welfare Union, Goa.

INDUSTRY :

Iron Ore Mining.

STATE :

Goa, Daman and Diu.

Bombay, the 7th October, 1977

AWARD

The Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in exercise of its powers conferred under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the following dispute to this Tribunal by its order No. L-29025/8/73-LRIV dated 31-8-1973 :—

“Whether the following truck drivers are justified in claiming fitment in the grade and scale of pay as shown in column (3) against their respective names with effect from the 1st January, 1968 in respect of the implementation of the final recommendations of the Central Wage Board for Iron Ore Mining Industry having regard to the terms and conditions contained in the settlement arrived at between the company and the Union on the 30th January, 1968 under Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 ? If so, from what date ?

S. No.	Name of Driver	Category in which originally fitted	Category to which promoted in 1971
1.	Mr. Prabhakar Vengurlekar	VI	VII
2.	Mr. Ganesh Cotambikar	VI	VII
3.	Mr. Shrikant Valvoicar	VI	VII
4.	Mr. Anjunhe Venkatappa	VI (VII)	VIII
5.	Mr. Sadanand Pileinekar	VI	VIII
6.	Mr. Suryakant Gavande	VI	VII
7.	Mr. Shivaji Dhargalkar	VII	VIII
8.	Mr. Jayaeshwar Aldonkar	VI	VII
9.	Mr. Suryakant Chodankar	VI	VIII
10.	Mr. Babni Amonkar	VI	VIII
11.	Mr. Shaik Inus	VI	VII
12.	Mr. Chandrakan Curtorkar	VII	IX
13.	Mr. Narayan Palyenkar	VI	VII
14.	Mr. Ambrose Lawrence	VI	VII
15.	Mr. Nanco B. Gaoncar	VI	VII

The facts as disclosed in the statement of claim filed by the workmen are that the 15 workmen herein are engaged as Truck Drivers in the Iron Ore Mines of M/s. V. M. Salgaocar & Brother Pvt. Ltd. (hereinafter referred as 'the management'). The Government of India while accepting the recommendations of the Central Wage Board for Iron Ore Mining Industry by its resolution dated 3-6-1967 requested the employers to implement the recommendations of the Wage Board expeditiously. In pursuance of that direction from the Government the management herein entered into an agreement with the workmen on 16-1-1968 undertaking to implement the said

recommendations with effect from 1-1-1968. On 30-1-1968 a further agreement was arrived at between the parties whereby the workmen accepted the categorisation of truck drivers into grades VI, VII and VIII as suggested by the management. The pay scales for these 3 different categories were fixed in accordance with the recommendations of the Central Wage Board for Iron Ore Mining Industry. As per this agreement the categorisation of the Truck Drivers was not made according to the pay load of the Trucks Driven by them, but no different considerations. The General Secretary of the Goa Mining Labour Welfare Union by his letter dated 23-11-1970 requested the management to recast the categorisation of the Truck Drivers on the basis of the pay load of the vehicles driven by them. This principle the management accepted and on that basis fixed the pay of the Drivers in the categories 6, 7 and 8. The workmen for the first time on 1-10-1971 demanded that retrospective effect should be given to the categorisation of Truck Drivers on the basis of the pay load with effect from 1-7-1967 and on that basis the emoluments of the Truck Drivers should be fixed from that date. They claim difference in wages. The workmen contend that from 30-1-1968 to 1-1-1971 they were driving the same types of Trucks. It is further contended on behalf of the workmen that the settlement dated 30-1-1968 having been revoked with effect from 10-10-1968 they were free to demand fresh categorisation of the Truck Drivers on the new basis with effect from 1-1-1968 ignoring the earlier agreement. The management did not accede to this demand of the workmen. Both the parties applied to the Government for reference of this dispute for adjudication and on the basis of that joint application the present reference is made to this Tribunal.

The management in their written statement has taken the stand that the Union having unconditionally agreed to the categorisation of the Truck Drivers made on 30-1-1968 it should not be permitted to go back on that. They further stated that as per the settlement dated 1-1-1971 several Truck Drivers were given higher grades not on account of the rationalisation of the categorisation but by way of promotion. They say that on 1-1-1968 the Truck Drivers in question were not fit to hold the posts in the higher categories. For the aforesaid reasons the management prays that this reference may be answered against the workmen.

The evidence of Shri George Vaz, General Secretary, Goa Mining Labour Welfare Union besides that of two workmen was recorded on behalf of the workmen and the evidence of Shri V. N. Parankushan, Chief Superintendent, Central Workshop, Surla for the management. Both the parties addressed elaborate arguments on the points in issue. The case was then closed for orders. After the order was practically dictated, Shri P. K. Lele for the management reported on 7-10-1977 that this dispute has been amicably settled between the parties and requested this Tribunal to pass an Award in terms thereof. He files a Memorandum of settlement along with three enclosures appended to it marked as Exhibits 'A', 'B' and 'C'. Annexure Exhibit 'A' to this Memorandum of Settlement is a copy of the letter addressed by Shri George Vaz, General Secretary of the Union WW-1 to the management on 23-11-1970 which is marked as Ex. F-3 in the case suggesting that the Truck drivers should be categorised on the basis of the pay load of the vehicles they were asked to drive. Exhibit 'B' is the letter addressed by Shri Parankushan EW-1 suggesting to the management that the demand made by the workmen in Ex. E-3 might be accepted (which is marked as Ex. W-3 in the case) Exhibit 'C' to this Memorandum of Settlement sets out the amount due to each of the 15 Truck Drivers concerned in the dispute on account of the implementation of this rationalised categorisation from 1968. That settlement also shows the number of months for which each of the Drivers is entitled to claim the dues. I consider this compromise is beneficial to the workmen.

In the result this reference is answered in terms of the Memorandum of Settlement dated 3-10-1971; a copy of which along with the three annexures thereto is appended to this award. Each of the 15 workmen will be entitled to the amounts shown against his name in the Annexure marked Exhibit 'C' to the Memorandum of Settlement.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

AGREEMENT BETWEEN M/S. V. M. SALGAOCAR & BROTHER PRIVATE LIMITED AND FIFTEEN DRIVERS CONCERNED IN REFERENCE NO. CGIT-2/10 OF 1973

Representing the Employers:	Representing the Workmen:
Shri P. K. Lele	Shri George Vaz,
Industrial Relations Officer.	General Secretary,
	Goa Mining Labour Welfare,
	Union.

SHORT RECITAL

Exhibit 'A'

Whereas Goa Mining Labour Welfare Union (hereinafter referred to as the Union) vide its letter dated 23rd November, 1970, addressed to M/s. V. M. Salgaocar & Brother Private Limited (hereinafter referred to as the employers) requested the employers for the recategorisation of the drivers employed by them in their mining establishments. Annexed hereto is the Exhibit 'A' which is the copy of the said letter.

Exhibit 'B'

And whereas the Workshop Superintendent of the employers vide his note dated 3rd December, 1970, recommended to the employers for recategorisation of the drivers based on the payload of the vehicles driven by the respective drivers with effect from 1-1-1971. Annexed hereto is the Exhibit 'B' which is the copy of the said note.

And whereas the employers accepted the recommendation and reclassified the drivers with effect from 1-1-1971.

Exhibit 'C'

And whereas the fifteen drivers whose names are referred to in the Exhibit 'C' annexed to this agreement, represented by the Union raised claim for giving retrospective effect to the categorisation from 1-1-1968.

And whereas the Union and the employers could not come to any agreement on the issue and agreed to make application to the Government of India for referring the matter to the Industrial Tribunal under the provisions of Section 10(2) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Exhibit 'D'

And whereas the Central Government vide their order No. L-290218/73-LR(IV) dated 31st August, 1973 referred the matter to the Central Government Industrial Tribunal No. 2. annexed hereto is the copy of the said order.

And whereas pursuant to subsequent discussions and negotiations held the parties have arrived at the following agreement to the intent that it shall be binding on them.

Now this agreement witnesseth and it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows:—

TERMS OF AGREEMENT

1. The employers agree to pay each driver whose name is shown at Column 2 of Exhibit 'C' an officiating allowance (being the difference of the salary in the scale in which the driver should have been fitted and the scale in which he was actually fitted in 1968). The amount of officiating allowance per month is shown in column 3 of the Exhibit. The number of months for which he is entitled to this allowance is shown in column 4 and the total amount payable to him is shown in column 5 of the Exhibit.

2. The Union agrees on behalf of the fifteen drivers that the sum mentioned in Clause 1 above will be the full and final settlement towards any claim arising out of the Reference CGIT-2/10 of 1973.

3. The Union and the Employers agree to file this agreement before the Honourable Industrial Tribunal requesting him to give Consent Award based on the Terms of Agreement.

Representing the Employers	Representing the Workmen
(P. K. Lele)	(George Vaz)

Witness : 1. B. N. Guonkar

Witness : 2. Soryakant Chodankar

Vasco da Gama.

October 3, 1977.

EXHIBIT 'A'

GOA MINING LABOUR WELFARE UNION

Register No. 4 (Goa) 1963 :—Indian Trade Union Act, 1926
Affiliated to the All India Trade Union Congress

No. SAL/TD/14/1970

Messrs V. M. SALGAOCAR & BRO., PVT. LTD.,
VASCO DA GAMA.

ASSONORA

BARDEZ, GOA.

Date : 23-11-1970

Dear Sirs,

SUBJECT :—Proper designation of Drivers into the Drivers Grades as per the agreement Memorandum of Settlement dated 30-1-1968.

You will recall that we had come to an agreed CATEGORISATION of Mining Employees which is enclosed as an Annexure to the Memorandum of Settlement in FORM 'H' signed on 30-1-1968. Hereafter the workmen were designated to the Grades as earmarked. This work was done in great haste and because of this a number of individual disputes arose for proper categorisation.

There are in all the following grades for drivers :

L.V. Drivers—Grade V
Truck Driver—Grade VI
Truck Driver—Grade VII
Truck Driver—Grade VIII

While fixing the drivers into the Grades it was necessary to categorise the drivers into Grades on the basis of the type of Truck that had been allotted to Drivers. And it is necessary for the Company to rationalize the Drivers grades and come to an agreed categorisation for Drivers as per the type of Truck Driven.

It will be appropriate to Designate drivers to grades on the following basis :

Euclid Trucks	—Grade VIII	—170-8-210-10-260
Om Titano	—Grade VII	—155-6-185-7-220
Light Truck	—Grade VI	—130-5-180
Jeeps	—Grade V	—110-3-125-4-145

Our demands if met will not necessarily mean an increase in the Basic salary of the Drivers even if designated to a higher grade that they are today placed in.

For instance an OM TITANO Truck Driver is placed in Grade VI, as today categorised and are drawing varied Basic salaries of Rs. 165.00, Rs. 145.00, Rs. 135.00. If all are uniformly brought in the Grade VII which will be an appropriate grade for this type of Truck in most cases there will be no increase in Basic wages only the increment which is Rs. 5 in Grade VI will be Rs. 6 in Grade VII.

Please examine the cases in the light of the latest FITMENT CHART for Drivers as prepared for the Transport Section and agree to regard the drivers on the formula given above which will be both rationalising the Grades for Drivers and doing justice to drivers who are working on Heavy Trucks and put on the Light Truck Scales.

I would like the Management to convey their decision to me

It is a standing grievance of the OM TITANO Truck Drivers that they have been put on a light Truck scale and there is justification for this considering that the OM TITANO truck is a heavy truck next only to the Euclid Truck.

Yours faithfully,

C. C. Mr. Parankushan,
Workshop Superintendent,
Central Workshop, Surla,

Sd/-
GEORGE VAZ
General Secretary.

EXHIBIT 'B'

V. M. SALGAOCAR & BROTHER PVT. LIMITED

To : Administration Manager From Central Workshop,
Vasco da Gama.

Ref CWS/ADM/135/SF-5.

Dated 3rd December 1970.

SUBJECT :—Proper designation of drivers in the Drivers Grade as per the agreement/memorandum of settlement dated 30th January, 1968.

Ref : Your letter No. 56/ADM/14/70 of 25-11-1970

At the time of implementation of the Wage Board recommendations, we had categorised the Motor Vehicle Drivers into the following four grades :

- (1) Truck Drivers, Gr. "A" —W.B. Gr. VIII
Scale : Rs. 170-8-210-10-26 0.
- (2) Truck Drivers, Gr. "B" —W.B. Gr. VII
Scale : Rs. 155-6-185-7-220.
- (3) Truck Drivers, Gr. "C" —W.B. Gr. VI
Scale : Rs. 130- 5-180.
- (4) Light Vehicle Drivers —W.B. Gr. V
Scale : Rs. 110-3-125-4-129.

We had eliminated the trucks make names from the designation (e.g. Euclid Driver) as the driver was expected to drive a truck of specific capacity whether it was Euclid Dumper or a Bigben. During the course of time it is likely that Euclid dumper could be replaced by Indian dumper of similar capacity and so on.

In the circumstances it is not advisable to change the present designation and introduce again the same designation which we had discarded for the aforesaid reason. We could however, rationalise the drivers grades on the basis of trucks payload as detailed below ;—

Sr. No.	Capacity of truck	Corresponding WB Gr. and Scale	Remarks
1.	Trucks having carrying capacity 15 tons payload	WB Gr. VIII Rs. 170-8-210-10-260.	Presently our Euclid and Bigben dumpers fall in this category.
2.	Trucks having carrying capacity 12 to 15 tons payload.	W.B. Grade VII Rs. 155-6-185-7-220.	Presently our OM Titano trucks fall in this category.
3.	All other trucks carrying less than 12 tons payload.	W.B. Grade VI Rs. 130-5-180	Other medium motor vehicles like Water tankers, lubcars, etc.
4.	Light motor vehicles like jeeps, cars and Light trucks the unladen weight of which does not exceed 3.9 tonnes.	W.B. Grade V Rs. 110-3-125-4-145	

The above categorization should Satisfy the Union as then the OM drivers would get salaries in W. B. Gr. VII. We have following 12 OM Titano drivers who are presently in wage-board grade VI, Rs. 130-5-180 and who are receiving less than Rs. 155 as basic salary. The net financial burden would be around Rs. 150 p.m. in case the above proposal is accepted with effect from 1-1-1971.

EXHIBIT 'D'

New Delhi, the 31st August, 1973

ORDER

S.O. 3946.—Whereas the employers in relation to the management of Messrs. V. M. Salgaocar & Brother Private Limited and their workmen represented by Goa Mining Labour Welfare Union have separately applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), for reference to a Tribunal of an industrial dispute that exists between them in respect of the matter set forth in the said applications and reproduced in the Schedule thereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the following truck drivers are justified in claiming fitment in the grade and scale of pay as shown in column (3) against their respective names with effect from the 1st January, 1968 in respect of the implementation of the final recommendations of the Central Wage Board for Iron Ore Mining Industry having regard to the terms and conditions contained in the settlement arrived at between the Company and the Union on the 30th January, 1968 under section 2 (P) of the Industrial Disputes Act, 1947. If so, from what date?

Sl. No.	Name	Present basic (1970)	Increment for '71	Total (3&4)	Basic in 1971 as per new categorization	Net burden
1	2	3	4	5	6	7
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.	Ganesh Cotombicar	145	5	150	155	5
2.	Suryakant Gavande	135	5	140	155	15
3.	Sadanand Pilernekar	135	5	140	155	15
4.	Ambrose Lawrence	145	5	150	155	5
5.	Jayeshwar Aldonkar	145	5	150	155	5
6.	Shrikant Valvoicar	145	5	150	155	5
7.	Shaik Inus	145	5	150	155	5
8.	Prabhakar Vengurlekar	140	5	145	155	10
9.	Babruwan Gaonkar	140	5	145	155	10
10.	Conceicao J Dias	135	5	140	155	15
11.	Domingos Fernandes	135	5	140	155	15
12.	Narayan Paliencar	140	5	145	155	10
Net addition :					Rs.	115
13.	Bernardo Rodrigues (W/tanker driver)	119	3	122	130	8

(To be put in Gr. VI)

Trust this will be in order.

Sd/-

Superintendent

EXHIBIT 'C'
CALCULATIONS
OFFICIATING ALLOWANCE

Sr. No.	Name of Driver	Rates Officiating Allowance	No. of months	Amount
1.	Mr. Prabhakar Vengurlekar	25	36	900
2.	Mr. Ganesh Cotambikar	25	36	900
3.	Mr. Shrikant Valvoicar	25	36	900
4.	Mr. Anjunhea Venkatappa	40	36	1440
5.	Mr. Sadanand Pilernekar	25	36	900
6.	Mr. Suryakant Gavande	25	36	900
7.	Mr. Shivaji Dhargalkar	40	12	480
8.	Mr. Jayeshwar Aldonkar	25	36	900
9.	Mr. Suryakant Chodankar	40	27	1080
10.	Mr. Babni Amonkar	40	36	1440
11.	Mr. Shaik Inus	25	36	900
12.	Mr. Chandrakant Curtorkar	60	36	2160
13.	Mr. Narayan Palyenkar	25	32	800
14.	Mr. Ambrose Lawrence	25	36	900
15.	Mr. Nanco B. Gaonkar	25	36	900

Name of Driver	Category in which originally fitted	Category to which promoted in 1971
1. Mr. Prabhakar Vengurlekar	VI	VII
2. Mr. Ganesh Cotambikar	VI	VII
3. Mr. Shrikant Valvoicar	VI	VII
4. Mr. Anjunhea Venkatappa	VI (VII)	VIII
5. Mr. Sadanand Pilernekar	VI	VIII
6. Mr. Suryakant Gavande	VI	VII
7. Mr. Shivaji Dhargalkar	VII	VIII
8. Mr. Jayeshwar Aldonkar	VI	VII
9. Mr. Suryakant Chodankar	VI	VIII
10. Mr. Babni Amonkar	VI	VIII
11. Mr. Shaik Inus	VI	VII
12. Mr. Chandrakant Curtorkar	VII	IX
13. Mr. Narayan Palyenkar	VI	VII
14. Mr. Ambrose Lawrence	VI	VII
15. Mr. Nanco B. Gaonkar	VI	VII

[No. L-29025/8/73-LRIV]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

[No. L-29025/8/73-LR. IV/D. III B.]

MANJIT SINGH, Under Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1977

संकल्प

का. आ. 3947.—इस सचिवालय के 12 दिसम्बर, 1977 के संकल्प सं. 14/1/2/77-सी.एफ. में, पैरा 2 में, निम्नीलिखित को क्रम सं. 14 के रूप में जोड़ दिया जाए :

“14. श्री एस. के. रावसदस्य सचिव”

[सं. 14/1/2/77-सी. एफ.]

आर. सी. भार्गव, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 14th December, 1977

RESOLUTION

S.O. 3947.—In this Secretariat Resolution No. 14/1/2/77-CF, dated the 12th December, 1977, in paragraph 2 thereof the following may be added as serial No. 14 :

“14. Shri S. K. Rau.....Member Secretary”

[No. 14/1/2/77-CF]

R. C. BHARGAVA, Jt. Secy.